सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के कार्यान्वयन पर 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के कार्यान्वयन पर
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

विवरण	का संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii-x
अध्याय-I		
परिचय		
ग्रामीण विद्युतीकरण	1.1	1
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	1.2	1
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना	1.3	2
योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था	1.4	2
योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ	1.5	3
मध्य प्रदेश में योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति	1.6	4
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.7	6
लेखापरीक्षा मानदंड	1.8	6
लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली	1.9	6
परियोजनाओं का चयन	1.10	6
प्रवेश एवं निर्गमन सम्मलेन	1.11	7
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.12	7
अभिस्वीकृति	1.13	8
अध्याय-II		
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन		
योजना के कार्यान्वयन की स्थिति	2.1	10
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का निर्माण	2.2	10
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में कमियाँ	2.2.1	11
उपभोक्ता और डीटीआर मीटरिंग के लिए अपर्याप्त योजना	2.2.2	13
डीडीयूजीजेवाई के तहत कार्यों का निष्पादन	2.3	13
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप कार्य का निष्पादन नहीं होना	2.3.1	14
कार्यादेश में उचित प्रावधान शामिल न करने के कारण अधिक व्यय	2.3.2	15
परिसमापन क्षति लगाने में विफलता	2.3.3	16
परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी	2.3.4	17

अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में विफलता	2.3.5	18
परियोजनाओं का समापन एवं अनुमोदन	2.4	19
लाभार्थियों के आकड़े और समापन प्रतिवेदन में विसंगतियां	2.4.1	20
गुणवत्ता आश्वासन एवं निगरानी	2.5	21
परियोजनाओं की निगरानी में कमियाँ	2.5.1	21
आरईसी गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा बताई गई खामियों को ठीक न किया जाना	2.5.2	23
डैशबोर्ड और वितरण कंपनियों के अभिलेख के अनुसार विभिन्न घटकों में अंतर	2.5.3	24
अध्याय-III		
सौभाग्य का कार्यान्वयन		
योजना का संक्षिप्त विवरण	3.1	26
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करना	3.2	27
परियोजनाओं का क्रियान्वयन	3.3	28
उचित प्रक्रिया के बिना कार्य का आवंटन	3.3.1	29
अनुबंध के निष्पादन में कमियाँ	3.3.2	30
नवीन सेवा कनेक्शन प्रदान करने के कार्य के निष्पादन पर अतिरिक्त व्यय	3.3.3	30
सामग्री की अत्यधिक खरीद	3.3.4	31
बिना किसी कनेक्शन के आधारभूत संरचना का निर्माण	3.3.5	32
सौर ऊर्जा पैक की स्थापना में परिहार्य व्यय	3.3.6	33
योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार सामग्री उपलब्ध नहीं कराना	3.3.7	34
सौर ऊर्जा पैक की स्थापना के लिए योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करना	3.3.8	34
गलत आधार पर नकद पुरस्कार की प्राप्ति	3.3.9	35
गलत आधार पर अतिरिक्त अनुदान की प्राप्ति	3.3.10	36
आरईसी गुणवत्ता निगरानीकर्ता के प्रतिवेदन का पालन न करना	3.3.11	37
परियोजनाओं का समापन एवं अनुमोदन	3.4	38
निष्पादित मात्रा की तुलना में अधिक लाभार्थियों का दावा	3.4.1	38
वित्तीय प्रबंधन	3.5	39
'स्वयं निधि' के हिस्से के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने में विफलता	3.5.1	40
दोषपूर्ण ऋण व्यवस्था के कारण अतिरिक्त शुल्क का परिहार्य भुगतान	3.5.2	41
निगरानी प्रबंधन	3.6	41
परियोजनाओं की निगरानी में कमियाँ	3.6.1	42
आरईसी गुणवत्ता निगरानीकर्ता द्वारा बताई गई खामियों को ठीक न किया जाना	3.6.2	44
डैशबोर्ड और वितरण कम्पनियों के रिकॉर्ड के अनुसार विभिन्न घटकों में अंतर	3.6.3	44

अध्याय-IV			
लाभार्थी का सर्वेक्षण			
लेखापरीक्षा प्रेक्षण		1 to 7	47
अध्याय-V			
योजना उपरांत विश्लेषण			
निष्कर्ष			53
अनुशंसा			53
परिशिष्ट			
1.1	डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के तहत वितरण कम्पनियों में निष्पादित भौतिक घटकों का विवरण दिखाने वाला पत्रक	1.6	55
2.1	13 नमूना परियोजनाओं में डीडीयूजीजेवाई के कार्य निष्पादन का ब्योरा दिखाने वाला पत्रक	2.1	56
2.2	डीडीयूजीजेवाई के तहत डीटीआर और उपभोक्ताओं की मीटरिंग की दोषपूर्ण योजना को दर्शाने वाला पत्रक	2.2.2	57
2.3	डीपीआर में स्वीकृत लेकिन कार्यान्वयन से वंचित गांवों का ब्योरा दिखाने वाला पत्रक	2.3.1	58
3.1	सौभाग्य के तहत 13 चयनित परियोजनाओं में निष्पादित वित्तीय और भौतिक घटकों का ब्योरा दिखाने वाला पत्रक	3.1	59
3.2	वितरण कंपनियों में बिना टेंडर के कार्यों के निष्पादन का ब्योरा दर्शाने वाला पत्रक	3.3.1	60
3.3	सौर ऊर्जा पैक की अनुचित क्षमता की स्थापना का ब्योरा दर्शाने वाला पत्रक	3.3.8	61
4.1	लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र का प्रारूप	अध्याय IV	62

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य के विधान सभा के समक्ष रखे जाने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2014-15 से 2021-22 तक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और 2017-18 से 2021-22 (योजना के कार्यान्वयन की अवधि) तक प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के दौरान 'मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के कार्यान्वयन पर' निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण उन प्रकरणों पर आधारित हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा तत्व है। कृषि, उद्योग और किसी राज्य के समग्र आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि के लिए विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती विद्युत की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक कुशल, लचीला और वित्तीय रूप से स्वस्थ विद्युत क्षेत्र किसी राज्य के विकास और आम आदमी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की कुंजी माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता आधार में वृद्धि, जीवनशैली में बदलाव और खपत के पैटर्न के कारण विद्युत की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके लिए विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण नेटवर्क को लगातार मजबूत और बढ़ाने की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान के अनुसार, विद्युत एक समवर्ती विषय है। विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी का कर्तव्य है कि वह आपूर्ति के अधिदेशित क्षेत्र में एक कुशल, समन्वित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित करे और बनाए रखे, साथ ही अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार विद्युत की आपूर्ति करे। हालाँकि, विद्युत वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क में कम निवेश हुआ और परिसंपत्तियों का रखरखाव खराब रहा। इस प्रकार, वितरण नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत करने और सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्रदान करने के लिए वितरण कंपनियों का समर्थन करने के लिए विभिन्न योजनाएँ थीं।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने (दिसम्बर 2014 में) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की, जिसमें पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को शामिल करते हुए एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण उप-घटक के रूप में आरजीजीवीवाई के लिए स्वीकृत परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई में शामिल किया गया, जिसके अतिरिक्त उद्देश्य हैं, जैसे कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना; तथा वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडर तथा उपभोक्ताओं के अंत में मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसका संवर्धन करना।

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (सौभाग्य) भी शुरू की (अक्टूबर 2017)। इस योजना के दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करना, दूरदराज और दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटोवोल्टिक आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली, जहां ग्रिड विस्तार संभव या लागत प्रभावी नहीं है, और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करना शामिल है।

उपरोक्त दोनों योजनाओं में विद्युत वितरण अवसंरचना के निर्माण और 19.33 लाख घरों को नए विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए ₹ 4,694.95 करोड़ का व्यय शामिल था। सभी वितरण कंपनियो/ राज्य सरकार ने प्रमाणित किया (जुलाई/सितंबर/अक्टूबर 2018) कि उन्होंने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसमें शामिल बड़ी वित्तीय राशि और योजनाओं के बड़े सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस निष्पादन लेखापरीक्षा में इन योजनाओं के कार्यान्वयन की जांच की गई है।

लेखापरीक्षा ने बुनियादी ढांचे के कार्यों की आवश्यकता का आंकलन करने की प्रणाली, योजनाओं के तहत परियोजनाओं के निष्पादन और कार्यों के निष्पादन और गुणवत्ता की निगरानी के तंत्र की जांच की। योजनाओं के तहत 50 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाओं को विस्तृत जांच के लिए नमूना चयनित किया गया था।

डीडीयूजीजेवाई

विद्युत वितरण कंपनियो को भारत सरकार से परियोजनाओं की मंजूरी के लिए विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर परियोजनावार डीपीआर तैयार करना था और स्वीकृत डीपीआर के अनुसार कार्य निष्पादित करना था। हालांकि, विद्युत वितरण कंपनियो ने बिना किसी क्षेत्र सर्वेक्षण के डीपीआर तैयार कर ली। परिणामस्वरूप, स्वीकृत मात्रा के विरुद्ध निष्पादित कार्यों के विभिन्न घटकों में भारी अंतर हुआ।

डीपीआर, एसओआर के अलावा अन्य दरों पर तैयार किए गए थे । मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.) और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.) की नौ नमूना चयनित परियोजनाओं का मूल्यांकन ₹ 25.94 करोड़ अधिक था और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.) की चार नमूना चयनित परियोजनाओं का मूल्यांकन ₹ 2.73 करोड़ कम था।

ऊर्जा लेखांकन और उच्च-हानि वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा हानियों को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय आरंभ करने के लिए विद्युत आपूर्ति की मीटरिंग को आवश्यक माना जाता है। 89,310 डी.टी.आर. तथा 2,83,777 बिना मीटर के उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग की आवश्यकता के विरुद्ध, डिस्कॉम ने केवल 2,400 डी.टी.आर. (तीन प्रतिशत) तथा 1,02,614 उपभोक्ताओं (36 प्रतिशत) के लिए मीटरिंग की योजना बनाई। हालांकि, किसी भी डी.टी.आर. के लिए मीटरिंग नहीं की गई तथा केवल 25,982 बिना मीटर के उपभोक्ताओं (25 प्रतिशत) के लिए मीटरिंग की गई।

विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए योजना के तहत स्वीकृत 86 सबस्टेशनों के विस्तार के सापेक्ष, मात्र 55 सबस्टेशनों का विस्तार किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने इनमें से 17 सबस्टेशनों का विस्तार ₹ 7.12 करोड़ की लागत से स्वयं ही किया, जिससे योजना के तहत ₹ 4.27 करोड़ का अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी।

परियोजना का समय पर पूरा होना जरूरी है ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द ग्रिड से जोड़ा जा सके। हालांकि, यह देखा गया कि टर्नकी आधार पर दिए गए चार परियोजनाएं दो से 22 माह तक देरी से पूरी हुई। तीन परियोजनाओं में, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने टर्नकी ठेकेदारों के काम को रद्द कर दिया लेकिन ₹ 6.51 करोड़ की परिनिर्धारित क्षति नहीं वसूली।

वितरण कंपनियों को 2020-21 तक एटीएंडसी हानि को 15.50 से 23.00 प्रतिशत की सीमा में लाना था और प्रोत्साहन के रूप में ₹ 102.96 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान (परियोजना लागत का 15 प्रतिशत) प्राप्त करना था। हालाँकि, वर्ष 2020-21 में एटीएंडसी हानि 18.51 से 47.34 प्रतिशत की सीमा में अधिक रही और वितरण कंपनिया अतिरिक्त अनुदान का लाभ नहीं उठा सकीं।

पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के विवरण, परियोजना समापन प्रतिवेदन में प्रस्तुत एवं अनुमोदित विवरण तथा योजना डैशबोर्ड में उपलब्ध विवरण में भिन्नताएं पाई गई।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) कार्यों को क्रमशः परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत और 0.60 प्रतिशत की परामर्श फीस पर दिया, जो कि अनुमोदित पीएमए लागत 0.50 प्रतिशत से बहुत अधिक थी । इस प्रकार, नौ नमूना परियोजनाओं में ₹ 0.31 करोड़ की लागत म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा वहन की गई। इसके अलावा, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने आरईसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत, परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया की

निगरानी और समन्वय, परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन, एमआईएस और वेब पोर्टल को अपडेट करने का काम पीएमए को नहीं सौंपा।

यह अनुशंसा की जाती है कि वितरण कंपनियों को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षणों के आधार पर कार्यों की योजना बनानी चाहिए और स्वीकृत योजना के अनुसार योजना को लागू करना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन और वितरण कंपनियों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन और परियोजना निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। साथ ही, कार्यों के निष्पादन में देरी से बचा जाना चाहिए और वितरण कंपनियो को अनुबंध की शर्तों के अनुसार एलडी लगाना चाहिए।

सौभाग्य

विद्युत वितरण कंपनियों को भारत सरकार से परियोजनाओं की मंजूरी के लिए विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर परियोजनावार डीपीआर तैयार करना था और स्वीकृत डीपीआर के अनुसार कार्य निष्पादित करना था। लेकिन वितरण कंपनियों ने बिना किसी क्षेत्र सर्वेक्षण के एसओआर के अलावा अन्य दरों पर डीपीआर तैयार कर ली। परिणामस्वरूप, 13 नमूना चयनित परियोजनाओं का मूल्य ₹ 30.66 करोड़ अधिक आंका गया। सभी 50 परियोजनाओं की डीपीआर देरी से जमा की गई।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा योजना की लागत का 10 प्रतिशत 'स्वयं निधि' उपलब्ध कराने के आश्वासन के बावजूद, यह देखा गया कि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने इसके लिए ऋण लिया और उसे मार्च 2022 तक ₹ 24.65 करोड़ का परिहार्य ब्याज वहन करना पड़ा।

कार्यादेश जारी करने के स्तर पर भी कमियां पाई गई क्योंकि 4,080 एलओए 1,38,054 घरों के विद्युतीकरण के लिए ₹ 50.62 करोड़ रुपये की राशि बिना बोली आमंत्रित किए स्वीकृत कर दी गई और कार्य पूरा होने की तिथि या उसके बाद 860 घरों के विद्युतीकरण के लिए पांच एलओए जारी किए गए। कार्य आदेशों में सामग्री की आपूर्ति भी शामिल थी, जो एसओआर से अधिक दर पर थी।

नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उच्च दर पर उच्च विनिर्देशों के साथ अतिरिक्त आइटम शामिल किए और योजना के तहत प्रति कनेक्शन ₹ 3,000 की अधिकतम सीमा के विरुद्ध ₹ 3,514.90/ ₹ 4,461.38 प्रति कनेक्शन का व्यय किया, जिससे चार परियोजनाओं में ₹ 11.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अलावा, वितरण कंपनियो ने ₹ 27.60 करोड़ की आवश्यकता से अधिक सामग्री खरीदी, जो अप्रयुक्त रह गई।

दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित अविद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाला सौर ऊर्जा पैक और बैटरी बैंक स्थापित किया जाना था। राज्य में उपलब्ध सौर विकिरण को ध्यान में रखते हुए, 250 डब्ल्यूपी के सौर ऊर्जा पैक प्रदान किए जाने थे, जबकि वितरण कंपनियों ने केवल 200 डब्ल्यूपी के 2,964 सौर ऊर्जा पैक स्थापित किए।

डिस्कॉम ने नकद पुरस्कार (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. प्रत्येक को ₹ 100.50 करोड़) और ₹ 110.54 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के लिए योजना के पूरा होने की घोषणा समय से पहले कर दी, हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार, योजना के तहत कुछ कार्य योजना की घोषित समाप्ति तिथि के बाद किए गए थे।

परियोजनाओं के प्रबंधन और समय पर पूरा करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसियों को लगाया जाना था। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने किसी भी पीएमए को नहीं लगाया, जबकि

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने देरी से (25 फरवरी 2019) पीएमए नियुक्त किया, जबकि कार्य 31 मार्च 2019 तक पूरा हो गया था।

समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 16 माह से अधिक की देरी हुई। 11 परियोजनाओं में, विद्युत वितरण कंपनियों ने 3.30 लाख लाभार्थियों को कनेक्शन प्रदान किए लेकिन 4.16 लाख लाभार्थियों के लिए दावे दर्ज किए, जिससे ₹ 24.06 करोड़ का अतिरिक्त दावा हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि डिस्कॉम को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद ही डीपीआर तैयार करनी चाहिए और निष्पादन के दौरान भारी भिन्नताओं से बचने के लिए नवीनतम एसओआर के आधार पर तैयार करना चाहिए। उन्हें ऋण लेने के बजाय 'स्वयं के धन' के एक हिस्से के लिए राज्य सरकार से धन प्राप्त करना चाहिए। वितरण कंपनियों को निविदा प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री खरीदनी चाहिए और विद्युतीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति पर त्रुटिपूर्ण घोषणाएं दर्ज करने से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन और वितरण कंपनियों को योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन में गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन और परियोजना निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन से वितरण कंपनियों/ राज्य सरकार राज्य में सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त कर सकी और आम लोगों को इसका लाभ मिला। हालांकि, जैसा कि पाया गया कि घरों में मीटरिंग के साथ-साथ डीटीआर में कई कमियां हैं और अन्य अक्षमताएं हैं, जिसके कारण अनंतिम बिलिंग यानी अनुमान के आधार पर बिलिंग में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए, जब तक वितरण कंपनियाँ इन योजनाओं के माध्यम से नए जुड़े उपभोक्ताओं सहित अपने सभी उपभोक्ताओं से अधिकतम राजस्व प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो जाती तब तक वितरण कंपनियाँ लगातार बढ़ती एटीएंडसी हानि को नियंत्रित नहीं कर पाएंगी।

अध्याय-I

अध्याय-I

परिचय

1.1 ग्रामीण विद्युतीकरण

विद्युत हमारे जीवन के सभी पहलुओं के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसे एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और मानव विकास को गति देने की कुंजी है। ग्रामीण विद्युतीकरण को ग्रामीण विकास में तेजी लाने के समाधान के रूप में देखा जाता है। विद्युत कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों, खादी और ग्रामोद्योग, कोल्ड चेन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के लिए एक आवश्यक बुनियादी ढांचा है। 2006 की ग्रामीण विद्युतीकरण नीति में यह निर्धारित किया गया था कि विद्युत क्षेत्र के विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति करना है, जैसा कि 2003 के विद्युत अधिनियम की धारा 6 में अनिवार्य है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को इस उद्देश्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयासरत हैं। ग्राहक आधार में वृद्धि, जीवन शैली में परिवर्तन और खपत स्वरूप के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके लिए निरंतर सुदृढ़ीकरण और वितरण नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता है। यद्यपि, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) की खराब वित्तीय स्थिति के परिणामस्वरूप वितरण नेटवर्क में कम निवेश हुआ है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का रखरखाव और अनुरक्षण खराब रहा है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उप-पारेषण और वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बढ़ाना देना भी आवश्यक माना जाता है।

तदनुसार, भारत सरकार ने समय-समय पर गांवों के विद्युतीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरु कीं। दिसंबर 2014 में भारत सरकार ने पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को शामिल करते हुए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) नामक एक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य 100 और उससे अधिक की आबादी वाले गांवों का विद्युतीकरण था। इसके बाद, 2017 में, भारत सरकार ने सभी ग्रामीण परिवारों और शहरी गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) नामक एक और योजना शुरू की।

मध्य प्रदेश राज्य में डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) आयोजित की गई है। इन योजनाओं का संक्षिप्त परिचय जिसमें योजना के उद्देश्य, अनुदान स्वरूप और बनाए गए बुनियादी ढांचे के विवरण शामिल हैं, इस अध्याय में नमूना चयन विवरण सहित लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा पद्धति के साथ चर्चा की गई है।

1.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त और अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" (डीडीयूजीजेवाई) योजना शुरू की। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित घटकों को निष्पादित करने के लिए योजना तैयार की गई थी:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग की सुविधा प्रदान करते हुए कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना;

- वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर), फीडर और उपभोक्ता छोर पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण (एसटी एंड डी) बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बढ़ाना; तथा
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत 12वीं और 13वीं योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई में आरजीजीवीवाई को शामिल करके पूरा करना। आरजीजीवीवाई को 100 और उससे अधिक की आबादी वाले गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को कवर करने के लिए तैयार किया गया था।

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड (जिसे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड-आरईसी के नाम से जाना जाता था) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया (दिसंबर 2014)।

आरईसी ने योजना के सफल कार्यान्वयन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना निर्माण, निष्पादन, गुणवत्ता आश्वासन और निगरानी के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए। यह योजना राज्य में डिस्कॉम द्वारा लागू की जानी थी।

1.3 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

क्यूंकी शहरी गैर-विद्युतीकृत घर आर्थिक रूप से गरीब थे, अतः भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ, शहरी क्षेत्रों में शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) नाम से एक और योजना शुरू की (अक्टूबर 2017)। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित घटकों को निष्पादित करने के लिए योजना तैयार की गई थी :

- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना;
- सुदूर और दुर्गम गांवों/ घरों में गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटो वोल्टाइक-आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली प्रदान करना; और
- शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना। गरीब की श्रेणी के बाहर वाले शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया था।

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी परियोजना निष्पादन की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी थी। यह योजना राज्य में डिस्कॉम द्वारा लागू की जानी थी।

1.4 योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य की वित्त व्यवस्था नीचे **तालिका 1.1** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.1 वित्त व्यवस्था

क्र.सं.	एजेंसी	समर्थन/अनुदान की प्रकृति	समर्थन/अनुदान की मात्रा (परियोजना लागत का प्रतिशत)
1.	भारत सरकार	अनुदान	60

2.	राज्य/ डिस्कॉम	स्वयं का कोष	10
3.	ऋणदाता (एफआई/बैंक)	ऋण	30
4.	निर्धारित लक्ष्य पूरा करने पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण घटक का 50 प्रतिशत (30 प्रतिशत) अर्थात 15 प्रतिशत

*(**स्रोत:** डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजना के दिशानिर्देश)*

1.5 योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ

योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम की भूमिका और दायित्वों को नीचे फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है:

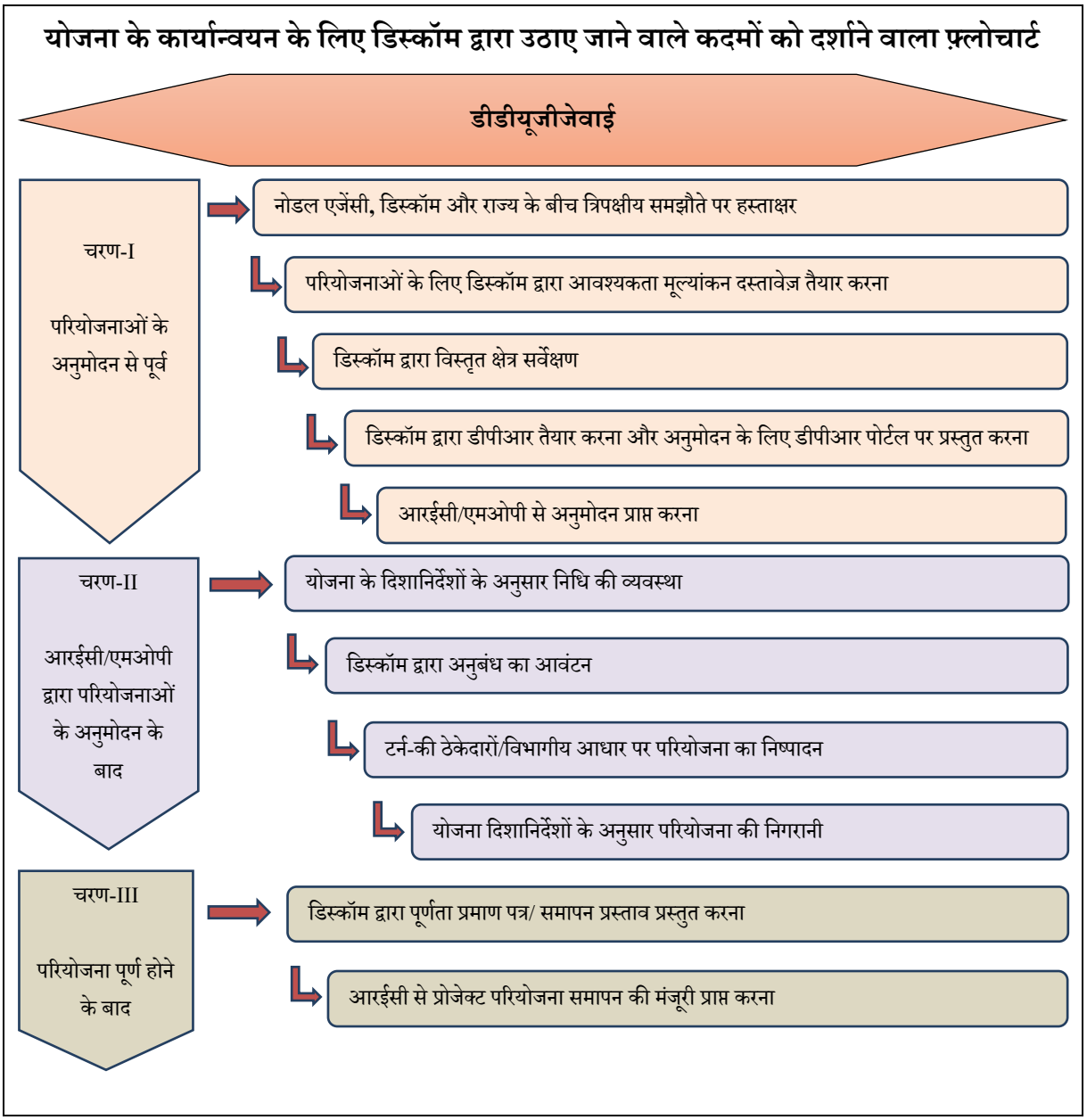

योजना के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को दर्शाने वाला फ़्लोचार्ट

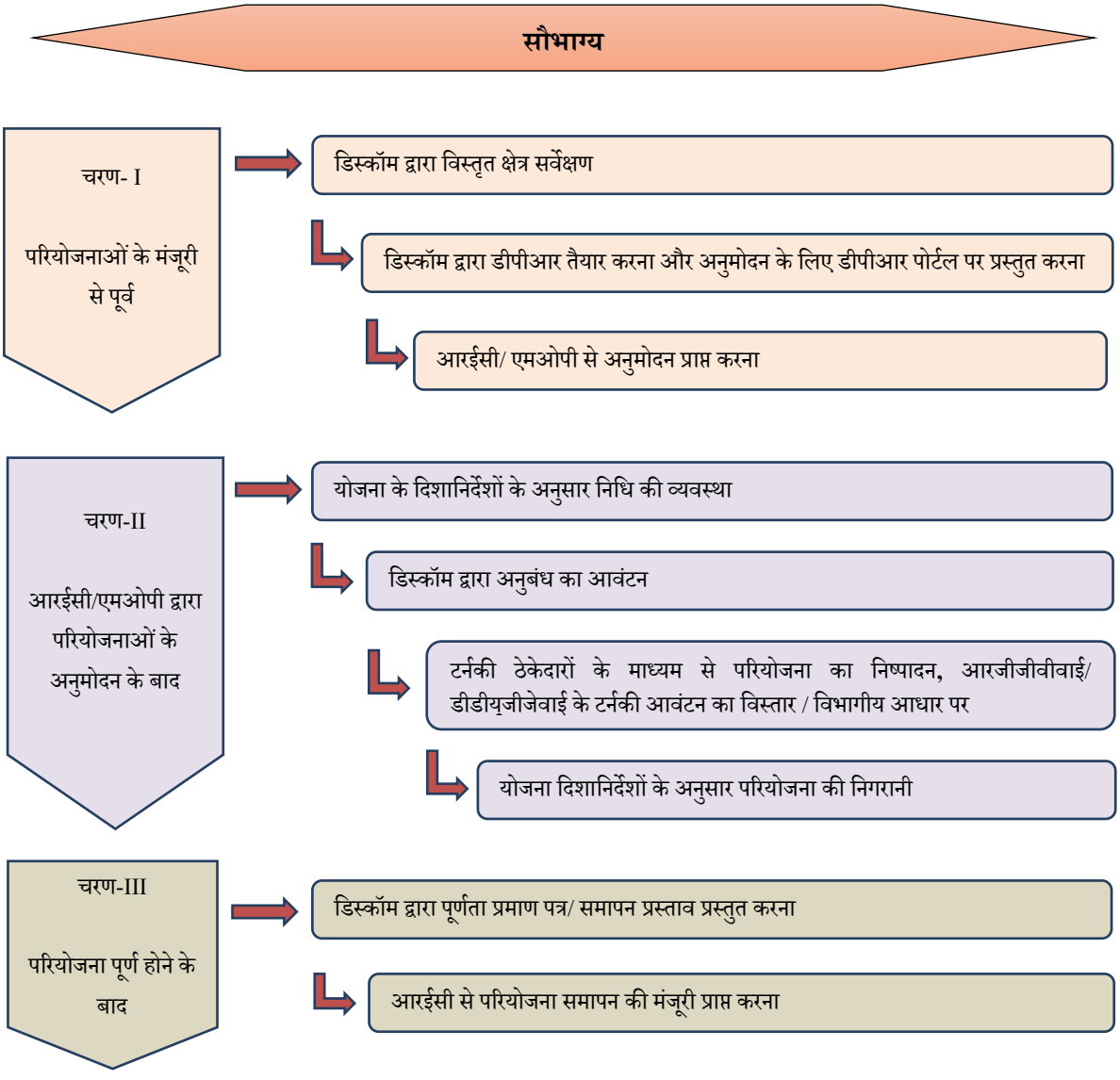

1.6 मध्य प्रदेश में योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्कॉम को योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना तैयार करने और योजना को क्रियान्वित करने की आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित तीन डिस्कॉम हैं:

- मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.);
- मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.) और
- मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.)।

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.मे.कं.लि.) तीनों डिस्कॉम की धारक कंपनी है। ये डिस्कॉम अपनी धारक कंपनी के साथ मध्य प्रदेश शासन (जीओएमपी) के स्वामित्व में हैं और ऊर्जा विभाग (विभाग),

मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती हैं। परियोजनाओं की संख्या और उनकी स्वीकृत लागत का डिस्कॉम-वार विभाजन नीचे **तालिका 1.2** में विस्तृत है:

तालिका 1.2: परियोजनाओं की संख्या और उनकी स्वीकृत लागत का डिस्कॉम-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	डिस्कॉम का नाम	डीडीयूजीजेवाई			सौभाग्य			कुल स्वीकृत लागत	कुल व्यय
		परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	वास्तविक व्यय	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	वास्तविक व्यय		
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	16	957.02	927.73	16	547.62	482.15	1,504.64	1,409.88
2.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	14	930.00	951.67	14	325.28	308.07	1,255.28	1,259.74
3.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	20	964.00	1,007.34	20	998.38	1,018.00	1,962.38	2,025.33
कुल		**50**	**2,851.02**	**2,886.75**	**50**	**1,871.28**	**1,808.22**	**4,722.30**	**4,694.95**

***(स्रोत:** आरईसी द्वारा जारी मंजूरी आदेश)*

डिस्कॉम ने विभिन्न बुनियादी ढांचे के निर्माण और इन योजनाओं के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप घरों को कनेक्शन प्रदान करने के लिए डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के माध्यम से उपरोक्त मंजूरी प्राप्त की। डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य में निर्मित बुनियादी ढांचे का डिस्कॉम-वार विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में दोनों योजनाओं (डीडीयूजीजेवाई के लिए 2014-15 से 2021-22 और सौभाग्य के लिए 2017-18 से 2021-22) की कार्यान्वयन अवधि के दौरान बनाए गए बुनियादी ढांचे की सारांशित समेकित स्थिति नीचे **तालिका 1.3** में दिखाई गई है:

तालिका 1.3: कार्यान्वयन अवधि के दौरान बनाए गए बुनियादी ढांचे की स्थिति

क्र.सं.	घटक का नाम	इकाई	डीडीयूजीजे वाई	सौभाग्य	कुल
1.	नया सबस्टेशन	संख्या	145	-	**145**
2.	सबस्टेशन का विस्तार	संख्या	314	-	**314**
3.	11 किलो वोल्ट (केवी) लाइन	सर्किट किलोमीटर (सीकेएम)	21,112	12,599	**33,711**
4.	वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर)	संख्या	24,612	15,204	**39,816**
5.	लो टेंशन (एलटी) लाइनें	सीकेएम	26,418	21,156	**47,574**
6.	अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की मीटरिंग	संख्या	1,80,966	-	**1,80,966**
7.	खराब मीटरों का प्रतिस्थापन	संख्या	2,37,515	-	**2,37,515**
8.	घरेलू कनेक्शन	संख्या	2,95,604	16,36,915	**19,32,519**

***(स्रोत:** डिस्कॉम का स्वीकृत समापन प्रतिवेदन)*

इस प्रकार, डिस्कॉम के बुनियादी ढांचे में 145 नए सबस्टेशन, 33,711 सीकेएम नई 11 केवी लाइनें, 47,574 सीकेएम एलटी लाइनें और 39,816 नए डीटीआर जोड़े गए। इसके अलावा, बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए 1,80,966 मीटर लगाए गए और 2,37,515 दोषपूर्ण मीटर बदले गए। सौभाग्य दिशानिर्देशों में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 47.75 लाख घर गैर-विद्युतीकृत थे। हालाँकि, डिस्कॉम ने अपने उत्तर (मार्च 2022) में कहा कि उपरोक्त आंकड़े अस्थायी थे। डिस्कॉम ने सौभाग्य के तहत 16,36,915 घरेलू कनेक्शन (57,994 शहरी गरीब कनेक्शन सहित) प्रदान किए थे और ग्रामीण घरेलू कनेक्शन अप्रैल 2015 में 50.01 लाख से बढ़कर मार्च 2022

में 77.09 लाख हो गए। अंततः, म. प्र. शासन ने प्रमाणित किया कि डिस्कॉम[1] द्वारा 22 अक्टूबर 2018 तक 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया।

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन कलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या:

- ढांचागत कार्यों की आवश्यकता का आंकलन करने और डीपीआर तैयार करने की प्रणाली पर्याप्त थी;
- परियोजनाओं का कार्यान्वयन किफायती, कुशल और प्रभावी था;
- निष्पादित कार्यों के निष्पादन और गुणवत्ता की निगरानी के लिए तंत्र पर्याप्त था; और
- योजना के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा किया गया।

1.8 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित थे:

- एमओपी और आरईसी द्वारा जारी योजना दिशानिर्देश;
- ग्रामीण विद्युतीकरण नीति 2006;
- आरईसी, राज्य शासन और डिस्कॉम के बीच त्रिपक्षीय समझौता;
- डीपीआर के स्वीकृत आदेश;
- योजनाओं के संबंध में एमओपी और आरईसी द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र/आदेश;
- स्वीकृत डीपीआर; और
- अनुबंध समझौते

1.9 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

योजना के इच्छित उद्देश्यों और निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन का विश्लेषण करने के लिए तीनों डिस्कॉम में निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 की अवधि के दौरान आयोजित की गई थी और इसमें परियोजना समापन सहित दोनों योजनाओं की पूरी कार्यान्वयन अवधि (अर्थात डीडीयूजीजेवाई के लिए 2014-15 से 2021-22 और सौभाग्य के लिए 2017-18 से 2021-22) को शामिल किया गया था।

योजनाओं के कार्यान्वयन का आंकलन करने के लिए, राज्य शासन के विभाग, डिस्कॉम के मुख्यालय (मुख्यालयों) के रिकॉर्ड और 13 नमूना परियोजनाओं के रिकॉर्ड की समीक्षा की गई।

1.10 परियोजनाओं का चयन

लेखापरीक्षा के उद्देश्य से डिस्कॉम की 50 परियोजनाओं को 'उच्च जोखिम' और 'अन्य' श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसमें व्यय के संदर्भ में शीर्ष पाँच प्रतिशत परियोजनाओं को 'उच्च जोखिम' माना गया था। सभी 'उच्च जोखिम' परियोजनाओं (तीन परियोजना) और 20 प्रतिशत 'अन्य' परियोजनाओं (10 परियोजना) को यादृच्छिक तरीके से लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था । इस प्रकार, कुल परियोजनाओं का 25 प्रतिशत, अर्थात

[1] म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.-30 सितंबर 2018, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.-28 जुलाई 2018 और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.-22 अक्टूबर 2018

50 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाओं[2] का चयन किया गया। नमूना चयनित परियोजनाओं का विवरण नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: तीन डिस्कॉम में नमूना चयनित परियोजनाओं का विवरण

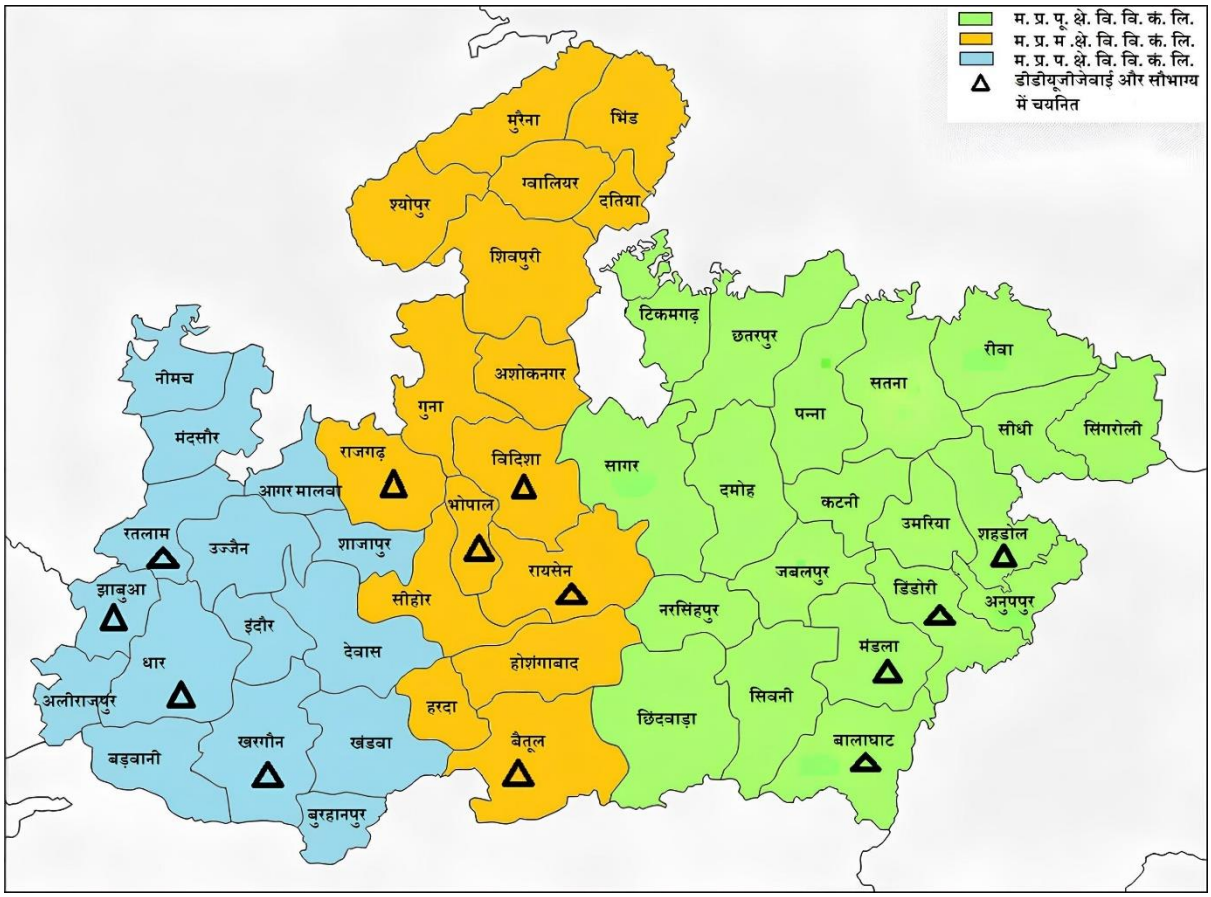

1.11 प्रवेश एवं निर्गम सम्मलेन

लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले विभाग, म.प्र. शासन और डिस्कॉम के प्रबंधन को लेखापरीक्षा के उद्देश्य, दायरे, कार्यप्रणाली आदि की जानकारी देने के लिए 22 अप्रैल 2022 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीनों डिस्कॉम के प्रबंधन से लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर जुलाई/ अगस्त 2023 में प्राप्त हुए। मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए निर्गम सम्मेलन 22 जून 2023 को आयोजित किया गया था। प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय शासन और प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं को संज्ञान मे लिया गया है।

1.12 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा निम्नलिखित अध्यायों में वर्गीकृत की गई है:

- अध्याय II : डीडीयूजीजेवाई का कार्यान्वयन
- अध्याय III: सौभाग्य का कार्यान्वयन
- अध्याय IV: लाभार्थी सर्वेक्षण
- अध्याय V : योजना पश्चात विश्लेषण

[2] म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.: 5 परियोजनाएं; म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.:4 परियोजनाएं; म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.:4 परियोजनाएं।

1.13 अभिस्वीकृति

निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन को सुविधाजनक बनाने में मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम प्रबंधन द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

अध्याय-II

अध्याय-II

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन

सारांश

अपर्याप्त और अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति की समस्या का समाधान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना निर्माण और उसके निष्पादन का विश्लेषण किया और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के निर्माण, आवंटन के साथ-साथ कार्यों के निष्पादन, वित्तीय अनुपालन, अवलोकन और योजना के समापन में कमियों को देखा। अध्याय में उजागर किए गए महत्वपूर्ण प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

- वितरण कंपनियों ने बिना किसी फील्ड सर्वेक्षण के डीपीआर तैयार किया था। परिणामस्वरूप, डीपीआर की स्वीकृत मात्रा के विरुद्ध कार्य निष्पादन में (-100) से 4,368 प्रतिशत तक की भिन्नता देखी गई।
- परियोजनाओं के आवंटन में 10 माह से लेकर 18 माह तक की देरी हुई और परियोजनाओं के पूरा होने में दो माह से लेकर 22 माह तक की देरी हुई।
- कार्यों को निष्पादित करते समय, योजना प्रावधानों/एलओए का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, वितरण कंपनियों द्वारा ₹ 0.63 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।
- वितरण कंपनियों ने लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई। परिणामस्वरूप, वितरण कंपनियाँ ₹ 102.96 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में विफल रही।

इस अध्याय में चर्चा किए गए लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष का सारांश नीचे दिया गया है:

- विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर डीपीआर तैयार नहीं किए गए थे।
- गांवों का विद्युतीकरण डीपीआर के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया।
- परियोजना का कार्यान्वयन ठेके प्रदान करने और कार्यों को पूरा करने में विलंब से घिरा हुआ था।
- कार्यों का निष्पादन योजना दिशानिर्देशों और एलओए के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।
- वितरण कंपनियाँ योजना के परिकल्पित लक्ष्य हासिल नहीं कर सकीं।

2.1 योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

यह योजना तीन वितरण कंपनियों में 50 परियोजनाएं तैयार करके लागू की गई थी। 13 नमूना चयनित परियोजनाओं में निष्पादित कार्य की संक्षिप्त स्थिति **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाई गई है।

योजना को लागू करने के लिए वितरण कंपनियों ने परियोजना-वार डीपीआर तैयार की और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और घरों तक बिजली प्रदान करने के लिए ₹ 2,851.02 करोड़ रुपये की मंजूरी प्राप्त की। ₹ 2,851.02 करोड़ की मंजूरी के विरुद्ध वितरण कंपनियों ने 50 परियोजनाओं में ₹ 2,886.73 करोड़ का व्यय किया। इसके अलावा, विस्तृत जांच के लिए चयनित 13 परियोजनाओं में ₹ 755.73 करोड़ की मंजूरी के विरुद्ध, वितरण कंपनियों ने ₹ 747.00 करोड़ का व्यय किया। स्वीकृत राशि और निष्पादित राशि वितरण का कंपनी-वार विवरण नीचे **तालिका 2.1** में दिया गया है:

तालिका 2.1: स्वीकृत और निष्पादित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वितरण कंपनी का नाम	कुल परियोजनाएँ			नमूना चयनित परियोजनाएं		
		परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	खर्च की गई वास्तविक राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	खर्च की गई वास्तविक राशि
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	16	957.02	927.73	5	336.44	320.65
2.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	14	930.00	951.67	4	330.92	333.58
3.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	20	964.00	1,007.33	4	88.37	92.77
	कुल	**50**	**2,851.02**	**2,886.73**	**13**	**755.73**	**747.00**

*(**स्रोत:** आर.ई.सी. द्वारा जारी किए गए मंजूरी आदेश और वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी।)*

लेखापरीक्षा ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना निर्माण और उसके निष्पादन का विश्लेषण किया और डीपीआर के निर्माण, आवंटन के साथ-साथ कार्य के निष्पादन, वित्तीय अनुपालन और निगरानी से संबंधित कमियों को देखा। इन मुद्दों पर उत्तरवर्ती ***कंडिका 2.2 से 2.6*** में चर्चा की गई है।

2.2 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का निर्माण

वितरण कंपनियों को बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता की पहचान करनी थी और डीपीआर तैयार करना था। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर को जिला/सर्कल/ज़ोन-वार तैयार किया जाना था और राज्य स्तरीय स्थायी समिति[1] (रा.स्तरीय स्थायी स.) द्वारा अनुमोदित किया जाना था। डीपीआर को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की निगरानी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रुरल एलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी.) को प्रस्तुत किया जाना था।

वितरण कंपनियों की नमूना चयनित परियोजनाओं के संबंध में डीपीआर प्रस्तुत करने और आरईसी की मंजूरी का तिथि-वार विवरण नीचे **तालिका 2.2** में संक्षेपित किया गया है:

[1] राज्य स्तरीय स्थायी समिति में मुख्य सचिव (अध्यक्ष के रूप में), ऊर्जा, वित्त, राजस्व, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और गृह विभागों के सचिव, मुख्य महाप्रबंधक (आरईसी) और तीन डिस्कॉम के प्रबंधन निदेशक शामिल हैं।

तालिका 2.2: डीपीआर प्रस्तुत करने और आरईसी की मंजूरी का विवरण

क्र.सं.	वितरण कंपनी का नाम	परियोजनाओं का नाम	डीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि	आर.ई.सी. द्वारा अनुमोदन की तिथि
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बैतूल, भोपाल, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा	26.05.2015	30.07.2015
2.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	धार, झाबुआ, खरगोन और रतलाम	25.05.2015	30.07.2015
3.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और शहडोल	26.05.2015	30.07.2015

*(**स्रोत:** वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और आर.ई.सी. द्वारा जारी मंजूरी आदेश)*

लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में इन डीपीआर की समीक्षा की और डीपीआर के निर्माण में निम्नानुसार विभिन्न कमियां देखी :

2.2.1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में कमियाँ

- विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण किसी भी परियोजना में साइट पर बनाए जाने वाले बुनियादी ढांचे की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करने के लिए प्राथमिक डेटा संग्रह की मूल प्रक्रिया है। योजना के दिशानिर्देशों में विस्तृत फील्ड सर्वेक्षणों के आधार पर डीपीआर तैयार करने का भी प्रावधान है। हालाँकि, यह देखा गया कि वितरण कंपनियों ने डीपीआर तैयार करने के लिए विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण नहीं किया। परिणामस्वरूप, कार्यों के विभिन्न घटकों के लिए वास्तविक निष्पादित मात्रा और डीपीआर में स्वीकृत मात्रा के बीच अत्यधिक भिन्नताएं थीं जैसा कि नीचे **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: वास्तविक निष्पादित मात्रा और स्वीकृत मात्रा के बीच भिन्नताओ का विवरण

क्र.सं.	वितरण कंपनी का नाम	नमूना चयनित प्रोजेक्ट का नाम	विभिन्न घटकों की मात्रा में भिन्नता				
			11 केवी लाइन (% में)	डीटीआर (% में)	एलटी लाइन (% में)	उपभोक्ता मीटरिंग (% में)	नये सेवा कनेक्शन (% में)
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बैतूल	4368	-37	65	-76	-79
2.		भोपाल	6	-32	70	-100	24
3.		रायसेन	18	77	399	-75	लागू नहीं*
4.		राजगढ़	12	-6	204	-100	-84
5.		विदिशा	-25	97	335	-100	लागू नहीं*
6.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	धार	5	57	-4	-62	0
7.		झाबुआ	-13	-34	152	-82	लागू नहीं*
8.		खरगोन	-26	-30	28	NA	-73
9.		रतलाम	-18	-16	22	-30	0
10.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बालाघाट	-16	11	57	-10	0
11.		डिंडोरी	248	7	9	-45	0
12.		मंडला	-10	-16	21	-46	95
13.		शहडोल	145	35	89	-26	759

* मद को डीपीआर में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए तुलना संभव नहीं थी।

*(**स्रोत**: वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)*

इसलिए डीपीआर में स्वीकृत मात्रा के विरुद्ध निष्पादित कार्यों के विभिन्न घटकों में (-100) से लेकर 4,368 प्रतिशत तक भारी भिन्नताएं थीं।

- ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया (अप्रैल 2015) कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा[2]) बिजली क्षेत्र में सभी केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करेगी। इसका उद्देश्य परियोजना के निर्माण से लेकर कार्यान्वयन और निगरानी तक पूरे जीवन चक्र में जन प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से शामिल करना था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 में से 10 नमूना चयनित परियोजनाओं[3] में वितरण कंपनियों ने डीपीआर के निर्माण के समय दिशा को नियुक्त/ परामर्श नहीं किया।

- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को नवीनतम लागू दरों की अनुसूची (एसओआर) यानी 2014-15 के आधार पर तैयार किया जाना था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीपीआर में शामिल कुछ प्रमुख घटकों[4] की दरें नवीनतम एसओआर के अनुरूप नहीं थीं। परिणामस्वरूप, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. की सभी नौ नमूना चयनित परियोजनाओं[5] में डीपीआर का मूल्यांकन ₹ 25.94 करोड़ से अधिक किया गया है और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. की सभी चार नमूना चयनित परियोजनाओं[6] में डीपीआर का मूल्य ₹ 2.73 करोड़ से कम किया गया है। इससे इन परियोजनाओं में गलत मंजूरी मिलने के अलावा निविदाओं का अनुमानित मूल्य अधिक/कम मूल्यांकित हो गया।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने कहा कि डीपीआर कम अवधि में तैयार की गई थी और डेस्क मूल्यांकन के आधार पर मात्रा मापी गई थी। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि जन प्रतिनिधियों से राय ली थी, हालांकि ये अभिलिखित नहीं था, जबकि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने कहा (अगस्त 2023) कि उसने डीपीआर को दिशा से अनुमोदित करवाया था। इसके अलावा, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने कहा कि डीपीआर की तैयारी में ली गई दरें लागत अनुमान के लिए थीं और परियोजना निर्माण पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने आगामी योजना के तहत परिकल्पित सभी घटकों को नवीनतम एसओआर के अनुरूप शामिल करने का आश्वासन दिया।

वितरण कंपनियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना दिशानिर्देशों के विपरीत, वितरण कंपनियों ने क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं किया था और डीपीआर दिशा के परामर्श के बिना तैयार की गई थी। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मामले में, दिशा का अनुमोदन आर.ई.सी. को डीपीआर प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, नवीनतम एसओआर का पालन न करने के कारण परियोजनाओं के अनुमान और मंजूरी त्रुटिपूर्ण थी।

---

[2] जिला विद्युत समिति का नाम बदलकर (26 जुलाई 2016) दिशा कर दिया गया।

[3] भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, झाबुआ, खरगोन, रतलाम, धार, शहडोल और बालाघाट।

[4] नया सबस्टेशन, अगस्त में एस/एस, 33 केवी लाइन, 11 केवी लाइन, एलटी लाइन और डीटीआर।

[5] भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, बैतूल, झाबुआ, खरगोन, रतलाम, धार।

[6] शहडोल, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी।

2.2.2 उपभोक्ता और डीटीआर मीटरीकरण के लिए अपर्याप्त योजना

डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अध्याय-I की कंडिका 2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण (एसटी एंड डी) बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बढ़ाने का प्रावधान करता है, जिसमें डीटीआर और उपभोक्ता छोर पर मीटरिंग भी शामिल है। इससे ऊर्जा लेखांकन के लिए एक तंत्र बनाने और उच्च हानि वाले क्षेत्रों की पहचान करने और नुकसान को कम करने की दिशा में उपचारात्मक उपाय शुरू करने में सुविधा होगी। योजना के दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि वितरण प्रणाली में सभी स्तरों पर ऊर्जा के निर्बाध लेखांकन और लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर और उपभोक्ता छोर पर मीटर की स्थापना महत्वपूर्ण है । नमूना चयनित परियोजनाओं की डीपीआर की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीटीआर की मीटरिंग और अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता मीटरिंग के कार्य के लिए प्रावधान अपर्याप्त थे।

वितरण कंपनियों ने 13 नमूना चयनित परियोजनाओं के तहत 89,310 डीटीआर और 2,83,777 बिना मीटर के उपभोक्ताओं की मीटरिंग की आवश्यकता के विरुद्ध मात्र 2,400 डीटीआर[7](तीन प्रतिशत) और 1,02,614 उपभोक्ताओं[8] (36 प्रतिशत) **(परिशिष्ट 2.2)** मीटरीकरण की योजना बनाई। इसके अलावा, 2,400 डीटीआर और 1,02,614 बिना मीटर के उपभोक्ताओं के लिए नियोजित मीटरिंग के विरुद्ध, किसी भी डीटीआर को मीटरीकृत नहीं किया गया था और केवल 25,982 बिना मीटर के उपभोक्ताओं (25 प्रतिशत) को मीटरीकृत किया गया । इस प्रकार, योजना पूर्ण होने के बाद भी 89,310 डीटीआर और 2,57,795 उपभोक्ता (91 प्रतिशत) बिना मीटर के रहे।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई/अगस्त 2023) कि योजना के तहत निधि की कमी के कारण डीटीआर का कोई मीटरीकरण नहीं हुआ और उपभोक्ताओं का कम मीटरीकरण हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मीटरीकरण के लिए योजना के तहत भारत सरकार से 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध था।

निष्कर्ष: विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के अभाव के कारण स्वीकृत डीपीआर के विरुद्ध निष्पादित कार्यों के विभिन्न घटकों में मात्रा में (-100) से 4368 प्रतिशत तक भिन्नता हुई । मीटरीकरण की आवश्यकता पर विचार किए बिना डीपीआर तैयार की गई थी और मूल्यांकन नवीनतम एसओआर के अनुरूप नहीं था।

अनुशंसा: निष्पादन में भारी भिन्नता से बचने के लिए वितरण कंपनियों को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद डीपीआर तैयार करना चाहिए। योजना के तहत परिकल्पित सभी घटकों को डीपीआर में शामिल किया जाना चाहिए और मूल्यांकन नवीनतम एसओआर के अनुरूप होना चाहिए।

2.3 डीडीयूजीजेवाई के तहत कार्यों का निष्पादन

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं को आर.ई.सी. से अनुमोदन के सूचना की तिथि से छह माह के भीतर आवंटित किया जाना आवश्यक था। इन परियोजनाओं को टर्न-की आधार पर आवंटित और निष्पादित किया जाना था और आवंटन पत्र (एलओए) जारी होने की तिथि से 24 माह के भीतर पूरा किया जाना था। नमूना चयनित परियोजनाओं के आवंटन का तिथि-वार विवरण नीचे **तालिका 2.4** में संक्षेपित किया गया है:

[7] पांच परियोजनाओं में- बैतूल, भोपाल, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा।

[8] नौ परियोजनाओं में- बैतूल, भोपाल, रायसेन, विदिशा, झाबुआ, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और शहडोल।

तालिका 2.4: नमूना चयनित परियोजनाओं के आवंटन का विवरण

क्र.सं.	वितरण कंपनी का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना के अनुमोदन की तिथि	परियोजना आवंटित करने की निर्धारित तिथि	निविदा की तिथि	एलओए की तिथि	एलओए जारी करने में देरी (माह में)
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	भोपाल	30.07.2015	31.01.2016	10.08.2016	28.12.2016	11
2.		विदिशा			10.08.2016	18.01.2017	11
3.		रायसेन			10.08.2016	28.12.2016	11
4.		राजगढ़			04.01.2017	27.07.2017	18
5.		बैतूल-I			10.08.2016	28.12.2016	11
6.		बैतूल-II			04.01.2017	18.05.2017	16
7.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	झाबुआ			14.12.2016	23.01.2017	12
8.		खरगोन			08.08.2016	14.12.2016	10
9.		रतलाम			08.08.2016	24.11.2016	10
10.		धार			14.12.2016	21.01.2017	12
11.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	शहडोल			10.08.2016	27.03.2017	14
12.		मंडला			30.01.2017	25.04.2017	15
13.		बालाघाट			28.03.2017	30.06.2017	17
14.		डिंडोरी			30.01.2017	02.05.2017	15

*(**स्रोत:** वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)*

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि परियोजनाओं के आवंटन में 10 माह से लेकर 18 माह तक की देरी हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह देरी मुख्यतः निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण हुई। इसके अलावा, शुरुआती निविदा के दौरान अधिक कीमतें मिलने के कारण कुछ परियोजनाओं में दोबारा निविदाएँ आमंत्रित करनी पड़ी।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रारंभ में आंशिक टर्नकी अनुबंध (टीकेसी) के माध्यम से कार्यों को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद, इन कार्यों को पूर्णतः टीकेसी माध्यम से निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। इस दुविधा के कारण डीडीयूजीजेवाई के तहत परियोजनाओं के निष्पादन में देरी हुई।

लेखापरीक्षा में वितरण कंपनियों में परियोजनाओं के आवंटन और निष्पादन की समीक्षा की गई। इस संबंध में देखी गई कमियों की चर्चा आगामी **कंडिका 2.3.1 से 2.3.5** में की गई है।

2.3.1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप कार्य का निष्पादन नहीं होना

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि 6,703 गांवों को विद्युतीकरण के लिए डीपीआर में शामिल किया गया था, लेकिन 13 परियोजनाओं में से 10 परियोजनों में वितरण कंपनियों द्वारा 3,193 गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया **(परिशिष्ट 2.3)**। इसके अलावा, 1,059 गांव जो डीपीआर में शामिल नहीं थे उन्हें इन 10 परियोजनाओं में योजना के तहत शामिल किया गया था।
- सिस्टम सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु 13 नमूना चयनित परियोजनाओं के डीपीआर में 86 सबस्टेशनों का संवर्द्धन प्रस्तावित किया गया था। यद्यपि, कार्यों के निष्पादन के दौरान योजना के तहत 13 परियोजनाओं में

केवल 55 सबस्टेशनों को संवर्धित किया गया। इसके अलावा, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने डीपीआर में शामिल 17 सबस्टेशन[9] को अपने स्वयं की ₹ 7.12 करोड़ की लागत से संवर्धित किया। परिणामस्वरूप, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. योजना के तहत ₹ 4.27 करोड़ अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी।

- सिस्टम सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु चयनित 13 परियोजनाओं की डीपीआर में 381 फीडरों के विभक्तिकरण के कार्य का अनुमोदन किया गया। हालाँकि, कार्यान्वयन के दौरान, योजना के तहत 13 परियोजनाओं में केवल 361 फीडरों का निर्माण किया गया। इनमें से 55 फीडरों की योजना डीपीआर में शामिल नहीं थी। इसके अलावा, राजगढ़ परियोजना के डीपीआर में शामिल नौ फीडरों का निर्माण म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा अपने स्वयं की ₹ 0.93 करोड़ की लागत से किया गया था। इस प्रकार, वितरण कंपनियां योजना के तहत ₹ 0.56 करोड़ अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी।

परियोजना समापन प्रतिवेदन में दर्शाया गया कि विद्युतीकरण हेतु उपरोक्त कार्य वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप किये गये। हालाँकि, वितरण कंपनियों द्वारा विचलन के लिए गाँव-वार/कार्य-वार औचित्य का ब्योरा नहीं रखा गया।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने कहा कि बचे हुए गांवों को बाद में सौभाग्य योजना के तहत शामिल किया गया। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ने उत्तर दिया (जुलाई/अगस्त 2023) कि सौभाग्य शुरू करने के बाद, डीडीयूजीजेवाई के बीओक्यू को कुछ गैर-महत्वपूर्ण कार्यों में कटौती के साथ फिर से तैयार किया गया और सौभाग्य के तहत आवश्यक कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। इसके अलावा, डीपीआर के तहत शामिल फीडरों को अन्य योजना के तहत पूरा किया गया और जो फीडर डीपीआर का हिस्सा नहीं थे, उन्हें स्थान की आवश्यकता के कारण अलग कर दिया गया था।

वितरण कंपनियों का यह तर्क कि एक योजना के तहत परिकल्पित कार्य के निष्पादन के दायरे में कटौती दूसरी योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गई थी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य अलग-अलग योजनाएं थीं, जहां डीडीयूजीजेवाई का उद्देश्य सिस्टम को मजबूत करना और सौभाग्य योजना का उद्देश्य घरेलू विद्युतीकरण था और दोनों योजनाओं के लिए 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध था।

2.3.2 कार्यादेश में उचित प्रावधान शामिल न करने के कारण अधिक व्यय

डीडीयूजीजेवाई में कार्यों के विभागीय निष्पादन के लिए, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा तैयार किए गए दर अनुबंध आवंटन[10](आरसीए) के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य प्रदान किए जाने थे। कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए आरसीए में विवेकपूर्ण ढंग से यह निर्धारित किया गया था कि सामग्री की आपूर्ति के लिए भुगतान, ठेकेदार के वास्तविक खरीद मूल्य या एसओआर मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य महाप्रबन्धक (क्रय) कॉर्पोरेट कार्यालय, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने आरसीए प्रसारित करते समय त्रुटिपूर्ण रूप से सामग्री का भुगतान एसओआर के अनुसार किया जाना निर्धारित किया।

[9] रायसेन में-बीकलपुर, गाडरवारा, गुरारिया, सेमरिया, उमरावगंज और पिपरिया-पुआरिया। बैतूल में-चंदू, जामदेही और प्रभात-पट्टन। राजगढ़ में-आसरेटा, गुलावता, लीमाचौहान, राधानगर, खुरी, लसुड़ियाभामा, आंदलहेड़ा, कोडक्या।

[10] आरसीए को केवल श्रम और परिवहन दरों के लिए अंतिम रूप दिया गया था।

परिणामस्वरूप, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के बैतूल वृत में ठेकेदारों को कार्य आरसीए शर्तों के अनुसार आवंटित किया गया था अर्थात एसओआर के अनुसार सामग्री का भुगतान किया जाना था। ठेकेदारों के बिलों की समीक्षा के दौरान एक्सएलपीई केबलों की खरीद चालान, पीसीसी पोल और मीटर बॉक्स में यह पाया गया कि ठेकेदारों का खरीद मूल्य निर्धारित दरों/ एसओआर से कम था। इस प्रकार म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को इन सामग्रियों पर ₹ 0.63 करोड़ का अधिक व्यय करना पड़ा।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि वास्तविक मूल्य और एसओआर दरों के बीच कम दरों पर सामग्री की आपूर्ति के लिए भुगतान का प्रावधान छोटी सामग्रियों के लिए लागू था, न कि प्रमुख बड़े सामग्रियों के लिए। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा लागू आरसीए में प्रमुख सामग्री के मामले में भी वास्तविक कीमत या एसओआर से जो भी कम हो पर भुगतान की व्यवस्था की गई थी। इसका पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

2.3.3 परिसमापन क्षति लगाने में विफलता

लेखापरीक्षा ने टर्नकी अनुबंधों के संबंध में परिसमापन क्षति की वसूली न करने के मामले पाए। इसके अलावा कुछ बचे हुए कार्यों को विभागीय स्तर पर सामग्री उपलब्ध कराकर ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया। यह देखा गया कि यद्यपि बचे हुए कार्यों को पूरा करने में देरी हुई, लेकिन परिसमापन क्षति आरोपित नहीं की गई।

- **टर्नकी कार्य:** निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार, यदि ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है तो उस स्थिति में नियोक्ता दिए गए कार्यों के दायरे को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह भी निर्धारित किया गया था कि देरी के मामले में प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर से परिसमापन क्षति, अधिकतम पांच प्रतिशत लगाया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने धीमी प्रगति के लिए तीन परियोजनाओं के संबंध में टर्नकी ठेकेदारों के कार्यों को रद्द कर दिया। आवंटित कार्य और रद्द किए गए कार्यों का परियोजना-वार विवरण नीचे **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: आवंटित और रद्द किए गए कार्यों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	टर्नकी ठेकेदार को आवंटित कार्य की राशि	कार्य की मात्रा का घटाया गया दायरा	घटाया गए कार्य की मात्रा के दायरा का प्रतिशत	एल डी (परिसमापन क्षति) नहीं/ कम लगाया गया
1.	रायसेन	26.58	5.01	18.85	1.33
2.	राजगढ़	98.75	14.24	14.32	3.84
3.	भोपाल	30.83	7.44	24.14	1.34
कुल					**6.51**

***(स्रोत:** वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)*

उपरोक्त से यह समझा जा सकता है कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने कार्य की मात्रा को 14 से 24 प्रतिशत तक कम कर दिया। साथ ही म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को कार्य कम कराने के बाद बचे हुए कार्य को खुद ही करना पड़ा। हालाँकि, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. धीमी प्रगति के लिए ठेकेदारों की गलती का हवाला देकर ऊपर उल्लेखित अनुबंध प्रावधान को लागू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, वितरण कंपनियों ने कार्यादेश के प्रावधान के

अनुसार एक[11] परियोजना में परिसमापन क्षति नहीं लगाई और दो[12] परियोजनाओं में कम क्षति आरोपित की। इस प्रकार, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने इन तीन परियोजनाओं में ₹ 6.51 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि सौभाग्य के क्रियान्वयन के कारण प्रबंधन की सुविधा के अनुसार कार्य रद्द किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन मामलों में कई नोटिसों के बाद भी कार्य की प्रगति धीमी रही और अंततः म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को कार्य का दायरा कम करना पड़ा और शेष कार्य स्वयं ही पूरा करना पड़ा।

2.3.4 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी

डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों कि कंडिका 9 और टर्नकी ठेकेदार (टर्नकी ठेकेदार) को जारी किए गए कार्यादेश के कंडिका 13 में यह निर्धारित किया गया था कि परियोजनाओं को एलओए/एलओआई जारी होने की तिथि से 24 माह के भीतर पूरा किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल 13 नमूना चयनित परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं दो माह से 22 माह की देरी से पूरी हुईं जैसा कि नीचे **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: परियोजनाओ के कार्यान्वयन मे देरी का विवरण

क्र. सं.	वितरण कंपनी का नाम	परियोजना का नाम	एलओए की तिथि	परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	वास्तविक समापन की तिथि	परियोजना के पूर्ण होने में देरी (माह में)	देरी के कारण
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बैतूल	28.12.16	27.12.2018	31.01.2020	13	टर्नकी ठेकेदार का खराब प्रदर्शन
2.		विदिशा	18.01.17	17.01.2019	31.03.2019	2	
3.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	खरगोन	14.12.16	13.12.2018	30.09.2020	22	टर्नकी ठेकेदार का खराब प्रदर्शन और राइट ऑफ वे
4.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बालाघाट	30.06.17	23.05.2019	31.03.2021	22	टर्नकी ठेकेदार का खराब प्रदर्शन

***(स्रोत:** वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी।)*

इस प्रकार, परियोजना के पूरा होने में देरी के परिणामस्वरूप योजना/ कार्यादेश के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ और योजना के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों को लाभ से वंचित होना पड़ा।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि ठेकेदार के खराब प्रदर्शन, स्थानीय हस्तक्षेप और कोविड-19 के कारण परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि टर्नकी ठेकेदार के खराब प्रबंधन के कारण परियोजनाओं में देरी हुई और टर्नकी ठेकेदार पर परिसमापन क्षति आरोपित कि गई। तथ्य यह है कि वितरण कंपनियों ने परियोजनाओं के निष्पादन की प्रभावी ढंग से निगरानी नहीं की किया जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई। परिणामस्वरूप, विलंब की अवधि के लिए उपभोक्ता योजना के लाभ से वंचित हो गए।

[11] रायसेन।

[12] रायगढ़ और भोपाल।

2.3.5 अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में विफलता

योजना के फंड संवितरण दिशानिर्देशों पर अध्याय IV के कंडिका 1.4 और 14.1 में भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान (ऋण घटक के 50 प्रतिशत का रूपांतरण यानी कुल फंड का 15 प्रतिशत) का प्रावधान है। इस अतिरिक्त अनुदान का लाभ उठाने के लिए, वितरण कंपनियों को (i) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार योजना को समय पर पूरा करना आवश्यक था; (ii) ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप पथ के अनुसार समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि (एटी एंड सी) में कमी हासिल करना; और (iii) राज्य शासन से अग्रिम रूप से स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी प्राप्त करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वितरण कंपनियाँ निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहीं जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- 13 नमूना चयनित परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं[13] दो से 22 माह की देरी से पूरी हुईं जैसा कि **कंडिका 2.3.4** में चर्चा की गई है।
- वितरण कंपनियों को 2020-21 तक एटी एंड सी हानि[14] को 15.50 से 23.00 प्रतिशत के बीच कम करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वितरण कंपनियां एटी एंड सी हानि को कम करने में विफल रहीं, जो 18.51 से 47.34 प्रतिशत के बीच रहा, जिसे निम्नलिखित **चार्ट** में दिखाया गया है:

ट्रेजेक्टरी एटी एंड सी हानि और उसके विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि दर्शाने वाला चार्ट

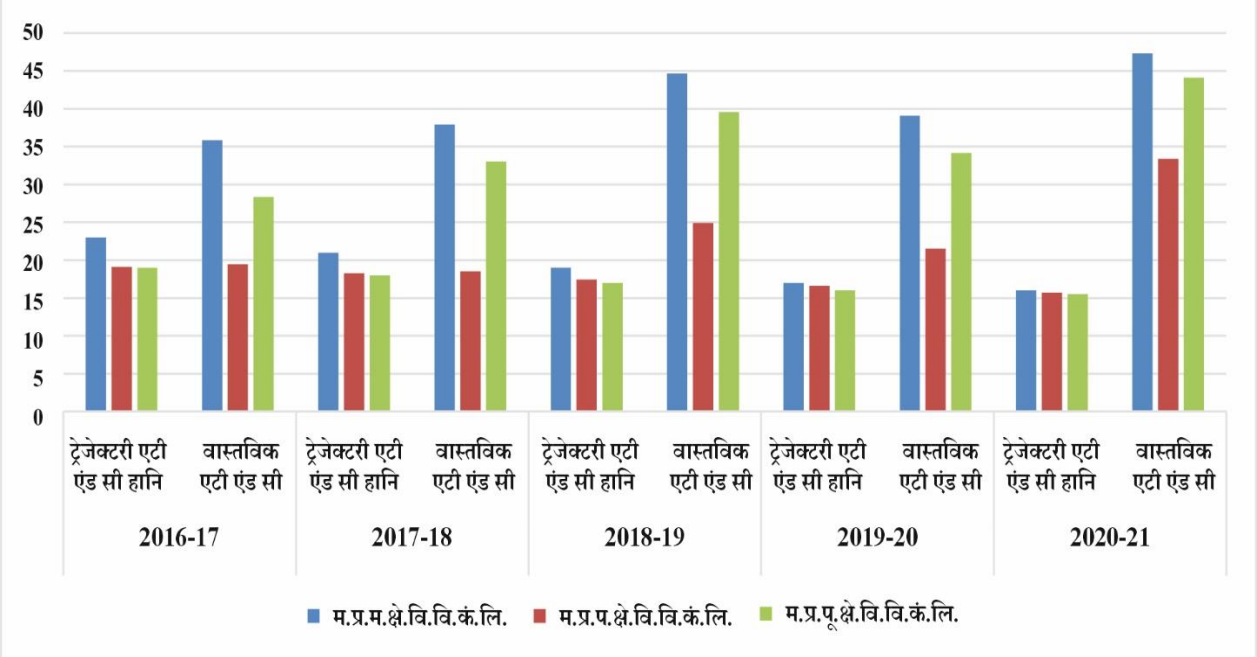

[13] बैतूल, विदिशा, खरगोन और बालाघाट।

[14] ट्रेजेक्टरी एमओपी द्वारा तय किया गया था।

- वितरण कंपनियों ने अग्रिम राजस्व सब्सिडी जारी करने के लिए राज्य शासन से संपर्क नहीं किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वितरण कंपनियों ने योजना के तहत उपलब्ध अतिरिक्त अनुदान का लाभ उठाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई, जो वितरण कंपनियों के उदासीन दृष्टिकोण को इंगित करता है। परिणामस्वरूप, वितरण कंपनियाँ 13 नमूना चयनित परियोजनाओं में ₹ 102.96 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में विफल रहीं।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने कहा कि अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए म.प्र. शासन द्वारा अग्रिम सब्सिडी जारी करना था। चूंकि म.प्र. शासन ने अग्रिम सब्सिडी जारी नहीं की, इसलिए वितरण कंपनियों को अतिरिक्त अनुदान प्राप्त नहीं हो सका।

हालाँकि, तथ्य यह है कि योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य शासन और वितरण कंपनियों के प्रबंधन द्वारा कोई समन्वित प्रयास नहीं किए गए।

निष्कर्ष: योजना के प्रावधानों और कार्यादेश के नियमों और शर्तों का पालन किए बिना गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। वितरण कंपनियों की निष्क्रियता के कारण, परियोजना के निष्पादन में देरी हुई और ठेकेदारों पर उनकी गलती के बावजूद परिसमापन क्षति आरोपित नहीं की गई।

अनुशंसा: कार्यादेश के नियमों और शर्तों के पालन के साथ योजना के प्रावधानों के अनुरूप गांवों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। वितरण कंपनियों को परियोजनाओं के निष्पादन में देरी से बचने के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए और अनुबंध की शर्तों के अनुसार परिसमापन क्षति की वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.4 परियोजनाओं का समापन एवं अनुमोदन

डीडीयूजीजेवाई के निधि संवितरण दिशानिर्देशों के अध्याय IV के कंडिका 13 में कहा गया है कि अनुदान घटक की अंतिम किश्त जारी करने के संबंध में वितरण कंपनियों द्वारा एक समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, कंडिका 15.1 में यह निर्धारित किया गया था कि वितरण कंपनियों को परियोजना पूरी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर समापन प्रतिवेदन जमा करना होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वितरण कंपनियों ने रिकॉर्ड पर बिना किसी कारण के 13 नमूना चयनित परियोजनाओं में से 10 में देरी से आरईसी को समापन प्रतिवेदन सौंपी। समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी का विवरण नीचे **तालिका 2.7** में दिया गया है:

तालिका 2.7: समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी का विवरण

क्र.सं.	वितरण कंपनी का नाम	परियोजनाओं का नाम	कार्य के भौतिक समापन की तिथि	समापन प्रतिवेदन जमा करने की लक्ष्य तिथि	समापन प्रतिवेदन जमा करने की वास्तविक तिथि	समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी (माह में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बैतूल	31.01.2020	30.01.2021	19.08.2020	-
2.		भोपाल	27.12.2018	26.12.2019	30.07.2020	7
3.		रायसेन	27.12.2018	26.12.2019	30.07.2020	7
4.		राजगढ़	26.07.2019	25.07.2020	15.02.2021	7
5.		विदिशा	31.03.2019	30.03.2020	15.02.2021	11
6.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	धार	11.12.2018	10.12.2019	19.12.2020	12

7.		झाबुआ	22.01.2019	21.01.2020	04.12.2020	11
8.		खरगोन	30.09.2020	29.09.2021	03.08.2021	-
9.		रतलाम	02.03.2018	01.03.2019	04.12.2020	21
10.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बालाघाट	31.03.2021	30.03.2022	28.12.2021	-
11.		डिंडोरी	30.12.2018	29.12.2019	28.05.2021	17
12.		मंडला	31.12.2018	30.12.2019	03.06.2021	17
13.		शहडोल	31.12.2018	30.12.2019	03.06.2021	17

*(**स्रोत:** डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देश और जानकारी, जैसा कि वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया है और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित किया गया है)*

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 10 विलंबित मामलों में देरी सात से 21 माह के बीच थी। 10 परियोजनाओं के समापन प्रतिवेदन जमा करने में देरी के कारण आरईसी द्वारा ₹ 28.91 करोड़ की अंतिम किस्त के दावे के प्रक्रिया में देरी हुई, जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2022)।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने टिप्पणी को स्वीकारते हुए मामले का संज्ञान लिया।

2.4.1 लाभार्थियों के आंकड़े और समापन प्रतिवेदन में विसंगतियां

डीडीयूजीजेवाई के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थियों को नई सेवा कनेक्शन प्रदान करना और दोषपूर्ण मीटरों को बदलना/ बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को मीटर लगाना शामिल है। वितरण कंपनियों ने योजना में नए सेवा कनेक्शन/ मीटरिंग कार्य निष्पादित किए हैं। म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों के आंकड़े और आरईसी को प्रस्तुत समापन प्रतिवेदन में विसंगतियां देखीं। विसंगतियों का विवरण नीचे **तालिका 2.8** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.8: लाभार्थियों के आंकड़ों मे विसंगतियों का विवरण

क्र. सं.	वितरण कंपनी का नाम	परियोजनाओं का नाम	नए सेवा कनेक्शन		उपभोक्ता मीटरिंग	
			उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार लाभार्थियों की संख्या	समापन प्रतिवेदन के अनुसार लाभार्थियों की संख्या	उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार लाभार्थियों की संख्या	समापन प्रतिवेदन के अनुसार लाभार्थियों की संख्या
1.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बालाघाट	-	-	59,940	64,345
2.		शहडोल	650	1,521	10,933	17,990
कुल			**650**	**1,521**	**70,873**	**82,335**

*(**स्रोत:** वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)*

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि शहडोल परियोजना में नए सेवा कनेक्शन के मामले में लेखापरीक्षा को प्रदान की गई लाभार्थियों की संख्या से अधिक समापन प्रतिवेदन में 871 (1,521-650) लाभार्थियों को दर्शाया गया था। इसके अलावा, बालाघाट और शहडोल परियोजनाओं में मीटरों की स्थापना/ प्रतिस्थापन के मामले में लेखापरीक्षा को प्रदान की गई लाभार्थियों की संख्या से अधिक समापन प्रतिवेदन में 11,462 (82,335-70,873) लाभार्थियों को दर्शाया गया था। इस प्रकार, आरईसी के समक्ष 12,333 लाभार्थियों के लिए ₹ 2.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दावा किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने कहा कि मिलान किया जाएगा और परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। हालाँकि, यह अभी तक अप्राप्त है (अगस्त 2023)।

निष्कर्ष: वितरण कंपनियों ने देरी से समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा संधारित आंकड़ों में विसंगतियां थीं।

अनुशंसा : म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा आरईसी को समापन प्रतिवेदन जमा करने से पहले आंकड़ों का मिलान करना चाहिए और वितरण कंपनियों को समयसीमा का पालन करना चाहिए।

2.5 गुणवत्ता आश्वासन एवं निगरानी

योजना के गुणवत्ता निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार, वितरण कंपनियाँ डीडीयूजीजेवाई कार्यों के तहत गुणवत्ता बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक व्यापक गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण योजना तैयार करेगी । गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण योजना आंशिक टर्नकी और कार्यों के विभागीय निष्पादन के मामले में, जैसा भी मामला हो, टर्नकी ठेकेदार या उपकरण आपूर्तिकर्ता/विक्रेता और निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध समझौते का एक अभिन्न अंग होगा। वितरण कंपनियों को यह सुनिश्चित करना था कि कार्यस्थल पर आपूर्ति की गई सामग्री/ उपकरण की गुणवत्ता और परियोजना के तहत कार्यों का निष्पादन गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण योजना के अनुसार हो।

लेखापरीक्षा ने योजना में गुणवत्ता आश्वासन दिशानिर्देशों के अनुपालन और परियोजनाओं की निगरानी की समीक्षा की। इस संबंध में मुद्दों पर उत्तरवर्ती **कंडिका 2.5.1, 2.5.2 और 2.5.3** में चर्चा की गई है।

गुणवत्ता संबंधी प्रकरण

2.5.1 परियोजनाओं की निगरानी में कमियाँ

दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर योजना की निगरानी के लिए विभिन्न प्राधिकरण स्थापित किए गए थे, जैसे:

- प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी और स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और समापन प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति[15]।
- परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियाँ (दिशा)।
- परियोजना प्रबंधन और इसके कार्यान्वयन में वितरण कंपनियों की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी की नियुक्ति।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने इन प्राधिकरणों द्वारा निगरानी पर निम्नलिखित टिप्पणी या विचार किए हैं जैसा कि नीचे **तालिका 2.9** में संक्षेप में दिया गया है:

[15] राज्य स्तरीय स्थायी समिति में मुख्य सचिव (अध्यक्ष के रूप में), ऊर्जा, वित्त, राजस्व, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और गृह विभाग के सचिव, मुख्य महाप्रबंधक (आरईसी) और तीन डिस्कॉम के प्रबंधन निदेशक शामिल हैं।

तालिका 2.9: निगरानी पर टिप्पणियों का विवरण

क्र.सं.	अवलोकन स्तर	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	**राज्य स्तरीय स्थायी समिति** डीडीयूजीजेवाई के लिए इसका गठन अप्रैल 2015 में किया गया था। राज्य स्तरीय स्थायी समिति आरईसी को डीपीआर की सिफारिश करने, परियोजनाओं की प्रगति की अवलोकन करने, गुणवत्ता नियंत्रण और समापन प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार थी।	➢ समिति का गठन करने वाला आदेश उस समय अवधि पर मौन था जिस पर समिति को बैठकें बुलानी थीं। इस प्रकार, अप्रैल 2015 और मार्च 2021 के बीच राज्य स्तरीय स्थायी समिति की केवल चार बार बैठक हुई। बैठकें डीपीआर को मंजूरी देने (18 जून 2015), मानक बोली दस्तावेज की मंजूरी (25 जून 2016), कार्यों के विभागीय निष्पादन (11 सितंबर 2018) और निष्पादित मापदंडों में बदलाव की मंजूरी (25 जून 2019) के लिए आयोजित की गईं। ➢ वितरण कंपनियों ने राज्य स्तरीय स्थायी समिति को बताया कि विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, हालांकि, वितरण कंपनियों ने विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण नहीं किया और इसे राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। ➢ राज्य स्तरीय स्थायी समिति ने कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान, समय पर अंतिम रूप देने और समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदि का अवलोकन नहीं किया, जिसमें कमियां थीं जो इस प्रतिवेदन में **कंडिका 2.3**, **2.4 और 2.5** में बताई गई हैं। शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया (अगस्त 2023)।
2.	**जिला स्तर पर जिला विकास समन्वय एवं अवलोकन समितियाँ** जिला स्तर पर, जिले के संसद सदस्य को अध्यक्ष बनाकर दिशा समितियां[16] गठित की गईं। जिले में चल रही परियोजनाओं के लिए, इन समितियों को परियोजनाओं के निर्माण से लेकर कार्यान्वयन और अवलोकन तक शामिल किया जाना था।	➢ दिशा डीपीआर तैयार करने में शामिल नहीं थी। ➢ दिशा को जिला स्तर पर कम से कम हर तिमाही बैठक करना आवश्यक था। 2015-16 से 2020-21 के दौरान, यह पाया गया कि संबंधित वितरण कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 13 नमूना जिलों में आवश्यक 312 बैठकों के विरुद्ध केवल कुल 66 बैठकें आयोजित की गईं। ➢ डीडीयूजीजेवाई के तहत निष्पादित कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता आश्वासन पर दिशा में चर्चा नहीं-की गई। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वितरण कंपनियों द्वारा योजना की प्रगति पर बैठकें आयोजित करने और चर्चा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि जन प्रतिनिधित्व से इनपुट लिया गया था, हालांकि वे रिकॉर्ड में नहीं हैं। म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि दिशा को डीपीआर से अवगत करा दिया गया था। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि डीपीआर को दिशा द्वारा अनुमोदित किया गया था। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि दिशा की बैठक सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर आयोजित की गई थी और सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को वितरण कंपनियों द्वारा संबोधित किया गया था। वितरण कंपनियों का तर्क सत्यापन योग्य नहीं है क्योंकि वितरण कंपनियों द्वारा प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाया नहीं गया है। इसके अलावा, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. की डीपीआर दिशा की मंजूरी के बिना आरईसी को प्रस्तुत की गई थी।
3.	**परियोजना प्रबंधन एजेंसी** परियोजना निर्माण और डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के कंडिका 11 में प्रावधान है कि परियोजना प्रबंधन एजेंसी को वितरण कंपनियों द्वारा परियोजना प्रबंधन में सहायता करने और परियोजना के समय पर	➢ म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने परियोजना लागत के क्रमशः 1.5 प्रतिशत और 0.60 प्रतिशत की परामर्श शुल्क पर परियोजना प्रबंधन एजेंसी कार्य सौंपा था, जो अनुमोदित परियोजना प्रबंधन एजेंसी लागत 0.50 प्रतिशत से काफी अधिक था। परिणामस्वरूप, नौ नमूना चयनित परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन एजेंसी की परामर्श शुल्क ₹ 0.31 करोड़ की राशि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा ही वहन की गई थी।

[16] सदस्यों में जिला कलेक्टर/जिला आयुक्त, जिले से राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, राज्य शासन से एक प्रतिनिधि, नगर पालिकाओं के सभी महापौर, जिलापंचायत के अध्यक्ष आदि शामिल हैं।

क्र.सं.	अवलोकन स्तर	लेखापरीक्षा अवलोकन
	कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन एजेंसी पर किए गए व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान (कार्य की लागत का 0.5 प्रतिशत तक) प्रदान किया जाना था । वितरण कंपनियाँ सीपीएसयू के पूल से नामांकन के आधार पर या खुली निविदा के माध्यम से परियोजना प्रबंधन एजेंसी का चयन कर सकते हैं। दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि बोली प्रक्रिया की अवलोकन और समन्वय, परियोजना योजना और कार्यान्वयन, गुणवत्ता अवलोकन, प्रबंधन सूचना प्रणाली और वेब पोर्टल को अपडेट करना अनिवार्य रूप से परियोजना प्रबंधन एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए।	➢ म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में परियोजना प्रबंधन एजेंसी की नियुक्ति के लिए जारी की गई निविदाओं में परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया का अवलोकन और समन्वय, परियोजना योजना और कार्यान्वयन और प्रबंधन सूचना प्रणाली और वेब पोर्टल को अपडेट करने का कार्य शामिल नहीं था, जो आरईसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत था। तदनुसार, इन कार्यों को शामिल किए बिना परियोजना प्रबंधन एजेंसी को कार्य सौंपे गए। इसके कारण, योजना के कार्यान्वयन में परियोजना प्रबंधन एजेंसी की भूमिका आनुपातिक रूप से कम थी। यह प्रबंधन सूचना प्रणाली के घटिया रखरखाव में भी परिलक्षित होता है जैसा कि अगली **कंडिका 2.5.3** में बताया गया है। परामर्श शुल्क के संबंध में, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि परामर्श के रूप में परियोजना प्रबंधन एजेंसी को किया गया भुगतान स्वीकृत लागत से कम था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना लागत के 0.10 प्रतिशत की सीमा तक परियोजना प्रबंधन एजेंसी का अतिरिक्त मूल्य म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा वहन किया गया था। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.ने लेखापरीक्षा आपतियों को स्वीकार किया। निविदाओं में परियोजना प्रबंधन एजेंसी के विभिन्न कार्यों को शामिल न करने के संबंध में, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने लेखापरीक्षा आपतियों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि अनिवार्य कार्यों को वितरण कंपनी का ही हिस्सा माना गया था। तथ्य यह है कि वितरण कंपनियों ने योजना के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।

*(**स्रोत:** डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देश और जानकारी, जैसा कि वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया है और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित किया गया है)*

2.5.2 आरईसी गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा बताई गई खामियों को ठीक न किया जाना

गुणवत्ता अवलोकन दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आरईसी ने डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत किए गए कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आरईसी गुणवत्ता नियंत्रक नियुक्त किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरईसी गुणवत्ता नियंत्रक ने 13 नमूना चयनित परियोजनाओं में 334 गांवों में परिसंपत्ति निर्माण पर 6,891 दोष (2,085 महत्वपूर्ण, 4,038 बड़े और 768 छोटे दोष) बताए[17]। हालाँकि, योजना के पूरा होने के 18 माह[18] (प्रतिवेदन जारी होने से 14 माह) बीत जाने के बावजूद, 226 गांवों में 764 दोष (154 महत्वपूर्ण, 302 बड़े और 308 छोटे दोष) अभी तक ठीक नहीं किए गए थे (सितंबर 2022)। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में इन दोषों के लम्बित रहने के कारण उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, आरईसी गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा बताए गए भारी दोष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि आरईसी गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा बताए गए दोषों की सीमा तक निम्न स्तरीय कार्य योजना के गुणवत्ता अवलोकन दिशानिर्देशों की उपेक्षा में निष्पादित किए गए थे। इसके अलावा, चूंकि संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा दोषों को ठीक किया जाना बाकी था, इसलिए बनाए गए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता निम्न स्तरीय बनी हुई है।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने बताया कि वितरण कंपनियों द्वारा दोषों को ठीक कर लिया गया था और आरईसी के साथ उनका समायोजन कर दिया गया था और प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाएंगे। हालाँकि, यह अप्राप्त रहे (अगस्त 2023)।

[17] निरीक्षण प्रतिवेदन आरईसी साक्ष्य पोर्टल से ली गई है।

[18] डीडीयूजीजेवाई के तहत अंतिम परियोजना बालाघाट परियोजना थी जो 31 मार्च 2021 को पूरी हो गई।

2.5.3 डैशबोर्ड और वितरण कंपनियों के अभिलेख के अनुसार विभिन्न घटकों में अंतर

डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन की प्रगति वितरण कंपनियों द्वारा अद्यतन/प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ऊर्जा मंत्रालय के डैशबोर्ड में दर्शाई जाती थी। वितरण कंपनियों के डीडीयूजीजेवाई के तहत सभी कार्य जून 2020[19] तक पूरे कर लिए गए थे। इस प्रकार, समापन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यों की प्रगति ऊर्जा मंत्रालय के पोर्टल पर प्रदर्शित होनी चाहिए थी।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डैशबोर्ड और समापन प्रतिवेदन में दर्शाई गई प्रगति (जून 2020) में भिन्नताएँ थीं, जैसा कि नीचे **तालिका 2.10** में दिखाया गया है:

तालिका 2.10: डैशबोर्ड और समापन प्रतिवेदन में दर्शाई गई प्रगति का विवरण

विभिन्न घटकों के नाम	भिन्नता		
	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
1	2	3	4
डीटीआर (संख्या में)	14 से 67	19 से 319	-18 से 31
एलटी लाइनें (किमी में)	5 से 232	21 से 319	46 से 149
11 केवी लाइन (किमी में)	-645 से 133	-38 से 539	58 से 696
उपभोक्ता मीटरिंग (संख्या में)	-671 से 3,753	-11,379 से 296	-3,132 से -60

***(स्रोत:** डैशबोर्ड पर दर्शाई प्रगति और वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)*

उपरोक्त भिन्नताएँ डीडीयूजीजेवाई योजना के कार्यान्वयन के दौरान पर्याप्त प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाए रखने में वितरण कंपनियों की विफलता को दर्शाती हैं।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने आपतियों को स्वीकार किया और उसे संज्ञान में लिया।

निष्कर्ष: म.प्र.शासन और वितरण कंपनियाँ योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र सुनिश्चित नहीं कर सकीं, परिणामस्वरूप, वितरण कंपनियों द्वारा निष्पादित कार्यों पर आरईसी गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा भारी विसंगतियां प्रतिवेदित की गई थीं और समापन प्रतिवेदन की तुलना में डैशबोर्ड में दर्शाए गए आंकड़ों में कई विसंगतियां थीं।

अनुशंसा: म.प्र.शासन और वितरण कंपनियों को योजना दिशानिर्देशों के पालन में गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन और परियोजना निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

[19] खरगोन और बालाघाट परियोजना को छोड़कर जो क्रमशः 30 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 को पूरी हुई थी।

अध्याय-III

अध्याय-III

सौभाग्य का कार्यान्वयन

सारांश

भारत सरकार ने सार्वभौमिक घरेलू कनेक्शन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी। लेखापरीक्षा ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना निर्माण और उसके निष्पादन का विश्लेषण किया और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के निर्माण, कार्य के आवंटन एवं निष्पादन, वित्तीय अनुपालन, निगरानी और योजना समापन में कमियाँ पायी। अध्याय में उजागर किये गये महत्वपूर्ण मुद्दे नीचे दिये गये हैं:

- वितरण कम्पनियों ने बिना किसी क्षेत्रीय सर्वेक्षण के डीपीआर तैयार किया था। परिणामस्वरूप, डीपीआर के तहत परिकल्पित 9,77,056 घरों के विद्युतीकरण की तुलना में 5,09,053 घरों का विद्युतीकरण ही किया गया।
- कार्यान्वयन के दौरान वितरण कम्पनियों ने योजना/ कार्यादेश के प्रावधानों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, वितरण कम्पनियों द्वारा ₹ 42.74 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।
- वितरण कम्पनियों ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निविदा के माध्यम से बोलियां आमंत्रित किए बिना 1,38,054 घरों के विद्युतीकरण के लिए ₹ 50.62 करोड़ रुपये के 4,080 आदेश जारी कर दिए।
- म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने योजना दिशानिर्देशों का उलंघन करते हुए ₹ 98.93 करोड़ से अधिक का ऋण लिया और उसे ₹ 24.65 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।
- वितरण कम्पनियों ने आरईसी के समक्ष योजनान्तर्गत 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण को जल्दी पूरा करने की असत्य घोषणा कर, अपात्र होते हुए भी नकद पुरस्कार और ₹ 250.53 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किया।

इस अध्याय में चर्चा किए गए लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष का सारांश नीचे दिया गया है:

- विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर डीपीआर तैयार नहीं की गई जिसके कारण निष्पादित मात्रा में बड़ी संख्या में भिन्नताएं हुई।
- योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए उचित निविदा प्रक्रिया के बिना घरों का विद्युतीकरण किया गया।
- योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कनेक्शन जारी करने के लिए घरों की पहचान किए बिना गांवों का विद्युतीकरण निष्पादित किया गया।
- म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा अपने स्रोत से निधि की व्यवस्था करने के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण ब्याज का परिहार्य बोझ पड़ा।
- योजना को जल्दी पूरा करने के असत्य दावे से वितरण कम्पनियों ने नकद पुरस्कार और अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किया।

3.1 योजना का संक्षिप्त विवरण

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अलावा, भारत सरकार ने सार्वभौमिक घरेलू कनेक्शन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत गरीब घरों तक अंतिम छोर कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य योजना बनाई और शुरू की (अक्टूबर 2017)। सुदूर या दुर्गम गांवों में गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटो वोल्टाइक आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली का भी प्रावधान था। विभिन्न गतिविधियों की समय-सीमा नीचे **तालिका 3.1** में दर्शाई गई है:

तालिका 3.1: विभिन्न गतिविधियों की समय-सीमा

क्र.सं.	गतिविधि	समयसीमा
1.	राज्यों द्वारा डीपीआर प्रस्तुत करना	6 नवंबर 2017
2.	डीपीआर का अनुमोदन	15 नवंबर 2017
3.	अनुबंधों का सौंपा जाना	31 दिसंबर 2017
4.	अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं को पूरा करना	31 दिसंबर 2018

*(**स्रोत:** सौभाग्य योजना दिशानिर्देश)*

सौभाग्य को लागू करने के लिए, तीनों वितरण कम्पनियों ने 50 परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार की और बुनियादी ढांचे के निर्माण और घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए ₹ 1,871.28 करोड़ रुपये की मंजूरी प्राप्त की । मंजूरी के विरुद्ध, वितरण कम्पनियों ने ₹ 1,808.22 करोड़ का कार्य निष्पादित किया। इसके अलावा, कुल 50 परियोजनाओं में से, 13 नमूना चयनित परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे के निर्माण और घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्वीकृत लागत और निष्पादित लागत क्रमशः ₹ 526.16 करोड़ और ₹ 495.75 करोड़ थी **(परिशिष्ट 3.1)**। परियोजनाओं का कंपनी-वार विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: कंपनी-वार परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वितरण कम्पनी का नाम	कुल परियोजनाओं का विवरण			नमूना चयनित परियोजनाओं का विवरण		
		कुल परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि[1]	वास्तविक खर्च की गई राशि	नमूना परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	वास्तविक खर्च की गई राशि
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	16	547.62	482.15	5	143.46	130.24
2.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	14	325.28	308.07	4	165.07	147.98
3.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	20	998.38	1018.00	4	217.63	217.53
कुल		**50**	**1,871.28**	**1,808.22**	**13**	**526.16**	**495.75**

*(**स्रोत:**आरईसी द्वारा जारी किए गए मंजूरी आदेश और वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)*

लेखापरीक्षा ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना निर्माण और उसके निष्पादन का विश्लेषण किया और डीपीआर के निर्माण, आवंटन के साथ-साथ कार्य के निष्पादन, वित्तीय अनुपालन और निगरानी के संबंध में कमियाँ पायी । इन मुद्दों पर आगामी **कंडिका *3.2* से *3.6*** में चर्चा की गई है ।

[1] आरईसी ने मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य को कुल ₹ 1,871.28 करोड़ (31.07.2018 को ₹ 872.64 करोड़ और 09.10.2018 को ₹ 998.64 करोड़) की मंजूरी दी और म.प्र. शासन ने मंजूरी लागत को तीनों वितरण कंपनियों के बीच वितरित किया ।

3.2 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करना

सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, वितरण कम्पनियों को जिले-वार डीपीआर तैयार करना था और उन्हें समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से आरईसी को ऑनलाइन जमा करना था। राज्य स्तरीय स्थायी समिति[2] द्वारा विधिवत अनुशंसित डीपीआर की भौतिक प्रतियां भी अभिलिखित और संदर्भ के लिए आरईसी को प्रस्तुत की जानी थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियों ने सभी 50 परियोजनाओं की डीपीआर, निर्धारित तिथि से 66 से 74 दिनों के विलंब से प्रस्तुत की, जैसा कि नीचे **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: डीपीआर प्रस्तुत करने मे देरी का विवरण

क्र.सं.	वितरण कम्पनी का नाम	परियोजनाओं की संख्या	डीपीआर प्रस्तुत करने की लक्ष्य तिथि	वेब पोर्टल पर जमा करने की वास्तविक तिथि	डीपीआर प्रस्तुत करने में देरी (दिनों में)	राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन की तिथि	आरईसी द्वारा डीपीआर अनुमोदन की तिथि
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	16	06.11.2017	19.01.2018	74	21.03.2018	31.07.2018
2.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	14	06.11.2017	11.01.2018	66	21.03.2018	31.07.2018
3.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	20	06.11.2017	11.01.2018	66	21.03.2018	31.07.2018

***(स्रोत:** सौभाग्य की योजना दिशानिर्देश और वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)*

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण, डीपीआर के निर्माण में जन प्रतिनिधियों के परामर्श और दरों की नवीनतम अनुसूची (एस.ओ.आर.) को लागू करने से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, वितरण कम्पनियों को लाभार्थियों की पहचान और घरों के ग्राम-वार विवरण के लिए विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, वितरण कम्पनियों ने योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना क्षेत्र सर्वेक्षण के डीपीआर तैयार की। इसके कारण, प्रारंभिक डीपीआर के मुकाबले वास्तविक निष्पादन में 1,42,841 से 2,07,780 घरेलू कनेक्शनों की भिन्नता देखी गयी जैसा कि नीचे **तालिका 3.4** में दिखाया गया है:

तालिका 3.4: विद्युतीकरण का विवरण

क्र.सं.	वितरण कम्पनी का नाम	नमूना चयनित परियोजनाओं की संख्या	प्रारंभिक डीपीआर के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत घरों की कुल संख्या	संशोधित डीपीआर के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत घरों की कुल संख्या[3]	विद्युतीकृत घरों की कुल संख्या
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	5	4,26,915	2,02,880	2,07,780
2.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	4	2,30,186	1,46,279	1,42,841
3.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	4	3,19,955	1,55,682	1,58,432
	कुल	**13**	**9,77,056**	**5,04,841**	**5,09,053**

***(स्रोत:** वितरण कम्पनियों द्वारा तैयार की गई डीपीआर और वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)*

[2] राज्य स्तरीय स्थायी समिति में मुख्य सचिव (अध्यक्ष के रूप में), ऊर्जा, वित्त, राजस्व, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और गृह विभाग के सचिव, मुख्य महाप्रबंधक (आरईसी) और तीन वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक शामिल हैं।

[3] डीपीआर को फील्ड सर्वेक्षण के बिना संशोधित किया गया था। हालाँकि, डीपीआर को संशोधित करते समय 1,61,826 घरों को बाहर कर दिया गया, जिन्हें डीडीयूजीजेवाई के तहत विद्युतीकृत किया जा रहा था।

- ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.म.), भारत सरकार ने निर्देश दिया (अप्रैल 2015) कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा)[4] को विद्युत क्षेत्र में सभी केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करनी है ताकि परियोजना के निर्माण से लेकर निष्पादन और निगरानी तक पूरे जीवन चक्र में जन प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने 13 नमूना चयनित परियोजनाओं में पाया कि वितरण कम्पनियों ने डीपीआर तैयार करने के लिए दिशा की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की। परिणामस्वरूप, जन प्रतिनिधियों से परामर्श नहीं किया गया, जिससे दिशा के गठन का उद्देश्य ही विफल हो गया।
- डीपीआर को नवीनतम यानी 2017-18 लागू दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) के आधार पर तैयार किया जाना था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीपीआर में दर्शाए गए प्रमुख घटकों[5] की दरें नवीनतम एस.ओ.आर. की दरों के अनुरूप नहीं थीं। परिणामस्वरूप, 13 नमूना चयनित परियोजनाओं की मूल्यांकन स्वीकृत राशि से ₹ 30.66 करोड़ अधिक था।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि सौभाग्य योजना पूर्ण करने के लिए बहुत कम समय मिला था, इसलिए विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। डीपीआर केवल एक लागत अनुमान था और एस.ओ.आर. दर का परियोजना निर्माण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। म.प्र.पू.क्षे. वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई/अगस्त 2023) कि डीपीआर तब प्रस्तुत की गई थी जब फील्ड सर्वेक्षण चल रहा था।

कड़ी समय सीमा का वितरण कम्पनियों का तर्क तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सौभाग्य दिशानिर्देश 20 अक्टूबर 2017 को जारी किए गए थे और वितरण कम्पनियों ने वास्तव में जनवरी 2018 में डीपीआर प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, वितरण कम्पनियों के पास क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए पर्याप्त समय था। इसके अलावा, योजना दिशानिर्देशों के विपरीत नवीनतम एस.ओ.आर. का पालन न करते हुए डीपीआर तैयार किए गए थे।

निष्कर्ष: विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के अभाव और नवीनतम लागू दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) को लागू नहीं करने के कारण, हर चरण में विद्युतीकृत होने वाले घरों की संख्या में अंतर था, जिसे आरईसी के अनुमोदन के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।

अनुशंसा: वितरण कम्पनियों को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद ही डीपीआर तैयार करना चाहिए। बड़ी संख्या में भिन्नताओं से बचने के लिए वितरण कम्पनियों को नवीनतम एस.ओ.आर. के आधार पर डीपीआर तैयार करना चाहिए।

3.3 परियोजनाओं का क्रियान्वयन

योजना के प्रावधानों के अनुसार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए वितरण कम्पनियाँ विभिन्न तरीकों को अपना सकती हैं जैसे कि विभागीय निष्पादन, आरजीजीवीवाई /डीडीयूजीजेवाई के तहत दिए गए टर्नकी कार्यों का विस्तार या

[4] जिला विद्युत समिति का नाम बदलकर (26 जुलाई 2016) दिशा कर दिया गया।

[5] 11 केवी लाइन और डीटीआर।

टर्नकी आधार पर नए कार्यों का आवंटन। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने विभागीय तौर पर कार्य निष्पादित किया जबकि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने सभी तरीके अपनाए।

3.3.1 उचित प्रक्रिया के बिना कार्य का आवंटन

सौभाग्य दिशानिर्देशों के कंडिका 8.3 में कहा गया है कि स्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण के कार्यों को वितरण कम्पनियों द्वारा ठेकेदारों को ई-टेंडरिंग के माध्यम से आवंटित किया जाएगा । लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.प.क्षे. वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने आवंटन में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने बिना लिखित औचित्य के, ई-टेंडर की प्रक्रिया अपनाए बिना या बोलियां आमंत्रित किए बिना 1,38,054 घरेलू कनेक्शनों के विद्युतीकरण के लिए ठेकेदारों को ₹ 50.62 करोड़ **(परिशिष्ट 3.2)** मूल्य के 4,080 कार्यादेश जारी किए जो कि योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।
- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. की एक परियोजना (धार) में कार्य पूरा होने की तारीख पर या उसके बाद 860 घरों के विद्युतीकरण के लिए पांच कार्यादेश (एल.ओ.ए.) जारी किए गए थे, जो कार्य के आवंटन में उचित प्रक्रिया की चूक को दर्शाता है।
- सौभाग्य दिशानिर्देशों के अध्याय IV के कंडिका 1 में यह निर्धारित किया गया है कि डीडीयूजीजेवाई में अपनाए गए निगरानी तंत्र का पालन किया जाएगा। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अध्याय II के कंडिका 11 में यह निर्धारित किया गया है कि वितरण कम्पनियाँ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) के पूल से या खुली बोली के माध्यम से किसी भी परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी.एम.ए.) का चयन कर सकती हैं । हालाँकि, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने सौभाग्य के तहत टीकेसी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के लिए निगरानी, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण परामर्श सेवाओं के लिए डीडीयूजीजेवाई के पी.एम.ए. के मौजूदा अनुबंध को बढ़ा दिया (25 फरवरी 2019)। यह योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था जो परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी.एम.ए.) के चयन के लिए केवल खुली प्रतिस्पर्धी बोली की अनुमति प्रदान करता था।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में मामले को देखने का आश्वासन दिया और वितरण कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में इसी तरह की घटनाएं दोबारा न हों। पी.एम.ए. की नियुक्ति के संबंध में, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि योजनांतर्गत बहुत कम समय मिला था, इसलिए पी.एम.ए. के लिए एक नई निविदा जारी करने का समय नहीं था, इसीलिए पी.एम.ए. के मौजूदा अनुबंध को कार्यादेश (एल.ओ.ए.) नियमों और शर्तों के अनुसार बढ़ाया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियों ने सौभाग्य के निष्पादन के लिए कार्य आवंटित करते समय भारत सरकार द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।

3.3.2 अनुबंध के निष्पादन में कमियाँ

- म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मुख्य व्यवसायिक कार्यालय ने योजना के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए दर अनुबंध आवंटन (आरसीए) को अंतिम रूप दिया और आवंटन जारी करने के लिए इसे वृत्त/ डिवीजन कार्यालयों में प्रसारित किया। आरसीए ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया कि ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री लागू दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) पर आपूर्ति की जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजगढ़ वृत्त में, कार्यों के निष्पादन के लिए मेसर्स श्याम इंडस पावर सॉल्यूशन (पी) लिमिटेड को 89 कार्यादेश जारी किए गए थे, जिसमें एस.ओ.आर. से अधिक दर पर सामग्री की आपूर्ति भी शामिल थी। जिसका औचित्य लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत अभिलेखों मे उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, उच्च दर पर कार्य आवंटित करने के कारण म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को ₹ 0.82 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। हालाँकि, इसकी प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई (अगस्त 2023)।

- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. की झाबुआ परियोजना में, सिस्टम को मजबूत करने के कार्यों के लिए मेसर्स इलेक्ट्रोमैक इंजीनियर्स, फरीदाबाद और मेसर्स ईएसपीएएन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दिल्ली (टीकेसी) के संयुक्त उद्यम को टर्नकी आधार पर एक कार्यादेश (23 जनवरी 2017) जारी किया गया था। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने झाबुआ परियोजना में सौभाग्य योजना को निष्पादित करने के लिए ₹ 8.50 करोड़ मूल्य के डीडीयूजीजेवाई के टीकेसी की कार्यादेश मात्रा को 26.78 प्रतिशत तक बढ़ा दिया (01 अक्टूबर 2018)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि टीकेसी के बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) का विस्तार करते समय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने 11,000 लाभार्थियों को कनेक्शन प्रदान करने का काम शामिल किया, जो टीकेसी के पहले बीओक्यू में मौजूद नहीं था। अतः इस कार्य का प्रावधान पूर्व अनुबंध में उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, कार्य का विस्तार करते हुए, बिना किसी औचित्य के मनमाने ढंग से लाभार्थियों को कनेक्शन प्रदान करने की दर ₹ 2,942 प्रति कनेक्शन निर्धारित की गई।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि कनेक्शन प्रदान करने की दर सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के साथ तर्कसंगत रूप से तय की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत रिकॉर्ड में कनेक्शन प्रदान करने के लिए दरों का कोई औचित्य/तर्काधार उपलब्ध नहीं था।

3.3.3 नवीन सेवा कनेक्शन प्रदान करने के कार्य के निष्पादन पर अतिरिक्त व्यय

योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, सर्विस लाइन केबल, सिंगल-फ़ेज़ मीटर, एलईडी बल्ब और अन्य संबंधित सहायक उपकरण की स्थापना के माध्यम से गैर-विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाना था। सौभाग्य के साथ संलग्न अनुलग्नक I में घरों को कनेक्शन प्रदान करने की लागत ₹ 3,000 प्रति कनेक्शन सीमित कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने क्षेत्र इकाइयों को कनेक्शन प्रदान करने का काम सौंपने के लिए दरें निर्धारित करने के लिए एक परिपत्र (06 फरवरी 2018) जारी किया था। इस परिपत्र में दो प्रकार के अनुसूची

शामिल थे, पहली अनुसूची मे अकवचित केबल का उपयोग करने वाले कनेक्शन के लिए ₹ 3,514.90 प्रति कनेक्शन की दर प्रदान की गयी थी, जबकि दूसरी अनुसूची मे कवचित केवल का उपयोग करने वाले कनेक्शन के लिए ₹ 4,461.38 प्रति कनेक्शन[6] की दर प्रदान की गयी थी, हालाँकि योजना में केवल अकवचित केबल का उपयोग प्रदान किया गया था। हालाँकि, ये दोनों दरें योजना के तहत प्रदान की गई दर (₹ 3,000 प्रति कनेक्शन) से अधिक थीं, जिसके लिए अभिलेख में कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य दो वितरण कम्पनियों ने खुद को ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.म.), भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के भीतर ही सीमित रखा। लेखापरीक्षा ने उच्च दर[7] के कारणों का विश्लेषण किया और पाया कि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अतिरिक्त/महंगी सामग्री शामिल की। चार परियोजनाओं में अतिरिक्त व्यय का विवरण नीचे **तालिका 3.5** में दिया गया है:

तालिका 3.5: परियोजनाओं में अतिरिक्त व्यय का विवरण

क्र.सं.	वृत्त का नाम	प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या	वृत्त द्वारा अनुसूची का पालन किया गया	मानदंडों के विरुद्ध उच्च दर (₹ प्रति कनेक्शन)	अतिरिक्त व्यय (₹ करोड़ में)
1.	शहडोल	31,437	**अनुसूची** -2	1,461.38	4.59
2.	मंडला	20,924	**अनुसूची** -2	1,461.38	3.06
		13,255	**अनुसूची** -1	514.90	0.68
3.	बालाघाट	34,995	**अनुसूची** -1	514.90	1.80
4.	डिंडोरी	25,617	**अनुसूची** -1	514.90	1.32
कुल					**11.45**

*(**स्रोत:** वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)*

इस प्रकार, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. को उच्च दरों पर कनेक्शन प्रदान करने के कारण चार नमूना चयनित परियोजनाओं में ₹ 11.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने कहा कि वितरण कम्पनियों ने कनेक्शन प्रदान करने में खर्च की गई अतिरिक्त राशि वहन की और आरईसी से इसकी मांग नहीं की गयी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अन्य दो वितरण कम्पनियों के विपरीत, केवल म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने कनेक्शन प्रदान करने पर अतिरिक्त लागत वहन की।

3.3.4 सामग्री की अत्यधिक खरीद

सौभाग्य के कार्यान्वयन के लिए, वितरण कम्पनियों ने कार्य के निष्पादन के लिए विभिन्न सामग्रियों की खरीद करी थी। इसके लिए वितरण कम्पनियों ने अपने नियोजित उपयोग के आधार पर सामग्रियों की आवश्यकता का आंकलन किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वितरण कम्पनियों ने विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद उनकी वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना सामग्री की खरीद की। परिणामस्वरूप, ₹ 27.60 करोड़ की निम्नलिखित सामग्री जो 2017-18

[6] कवच केबल के माध्यम से कनेक्शन ₹ 946.48 प्रति कनेक्शन महंगा था।

[7] पीवीसी केबल, अर्थिंग वायर, सर्विस लाइन सपोर्ट, विविध वस्तुएं।

से 2018-19 (सौभाग्य की कार्यान्वयन अवधि) के दौरान खरीदी गई थी**,** अप्रयुक्त रह गई (जुलाई/अगस्त 2022)। वितरण कम्पनियों के पास शेष अप्रयुक्त सामग्री का विवरण नीचे **तालिका 3.6** में दिया गया है:

तालिका 3.6: अप्रयुक्त सामग्री का विवरण

क्र.सं.	वितरण कंपनी का नाम	सामग्रियों का नाम	खरीदी गई मात्रा	सौभाग्य में उपयोग की गई मात्रा	सौभाग्य से परे उपयोग की गई मात्रा	शेष मात्रा (जुलाई/अगस्त 2022 तक)	मद की दर (₹ में)	सामग्री की शेष मात्रा का मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	पीवीसी अकवचित केबल	17,907	12,570.8	1,815	3,521	8,614	3.03
2.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	16 केवीए, डीटीआर	2,000	1,597	-	403	39,294	1.58
		बीपीएल सेवा कनेक्शन किट	2,00,000	1,92,297	-	7,703	1,470	1.13
3.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	25 केवीए डीटीआर	13,861	7,630	1,684	4,547	48,085	21.86
कुल								**27.60**

***(स्रोत:** वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी।)*

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने बताया कि वितरण कम्पनियों ने अपने नियमित संचालन एवं संधारण कार्यों में अधिकांश सामग्रियों का उपयोग किया था, जिसकी मांग आरईसी से नहीं की गयी थी और उपयोग से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाएंगे। विभाग ने वितरण कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी आगाह किया कि खरीद विवेकपूर्ण तरीके से की जाए।

सामग्री के उपयोग को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि वितरण कम्पनियों ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

3.3.5 बिना किसी कनेक्शन के आधारभूत संरचना का निर्माण

सौभाग्य दिशानिर्देशों के अध्याय II के कंडिका 4 में यह निर्धारित किया गया था कि सौभाग्य के तहत कनेक्शन प्रदान करने के लिए जहां भी मौजूदा आधारभूत संरचना अपर्याप्त है या उपलब्ध नहीं है, वहां अतिरिक्त आधारभूत संरचना[8] तैयार की जावे। तदनुसार आरईसी ने डीपीआर को मंजूरी देते समय स्पष्ट किया था कि सौभाग्य अंतर्गत मंजूर घरेलू विद्युतीकरण के लिए ही अतिरिक्त आधारभूत संरचना तैयार की जावे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियों ने 13 नमूना चयनित परियोजनाओं में से नौ परियोजनाओं[9] में कोई कनेक्शन दिए बिना 586 गांवों/बस्तियों में ₹ 30.47 करोड़ का व्यय कर 318.65 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) 11 किलो वोल्ट लाइन, 882.56 सीकेएम एलटी लाइन और 439 डीटीआर का निर्माण किया था। इस प्रकार, वितरण कम्पनियों ने दिशानिर्देशों/ मंजूरी के प्रावधानों का पालन किए बिना आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया।

[8] डीटीआर, लाइनें आदि।

[9] धार, झाबुआ, खरगोन, रतलाम, बैतूल, भोपाल, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि आधारभूत संरचना का निर्माण किसी भी योजना के माध्यम से सेवा कनेक्शन जारी करने के लिए और ट्रांसमिशन नेटवर्क का सुद्रढिकरण नए कनेक्शनों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था । म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि डीडीयूजीजेवाई/ सौभाग्य योजनाएं समानांतर रूप से चल रही थीं और कुछ मामलों में डीडीयूजीजेवाई में आधारभूत संरचनाओं का कार्य और सौभाग्य में कनेक्शन कार्य निष्पादित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक योजना का एक अलग उद्देश्य होता है। सौभाग्य का उद्देश्य घरेलू कनेक्शन प्रदान करना था और बुनियादी ढांचा केवल घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए ही बनाया जाना चाहिए।

3.3.6 सौर ऊर्जा पैक की स्थापना में परिहार्य व्यय

सौभाग्य दिशानिर्देशों के कंडिका 2.1 में कहा गया है कि ऑफ-ग्रिड कनेक्शन उन गांवों में प्रदान किया जाना था, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं थी । सौभाग्य दिशानिर्देशों के अध्याय- II परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन की कंडिका 2.6 में यह निर्धारित किया गया है कि दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों में, बैटरी बैंकों के साथ 200 से 300 वाट पीक (डब्ल्यूपी) के सौर ऊर्जा पैक प्रदान किए जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. की रायसेन परियोजना ने ₹ 0.73 करोड़ (औसत ₹ 17,622 प्रति इकाई की दर पर) की लागत पर 50 डब्ल्यू पी के 414 सौर ऊर्जा पैक स्थापित[10] किए थे। इसके बाद, इन सोलर पैक को 200 डब्ल्यू पी में उन्नत करने[11] के लिए वृत्त कार्यालय ने बैटरी और अन्य परिधीय उपकरणों का उन्नयन करने के लिए 150 डब्ल्यू पी क्षमता के पैक जोड़ने का काम ₹ 1.03 करोड़ (₹ 24,774 प्रति इकाई की औसत दर पर) की लागत से सौंपा । इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि कि 200 डब्ल्यू पी सौर ऊर्जा पैक की औसत दर ₹ 31,348 प्रति इकाई थी । इस प्रकार, 200 डब्ल्यू पी पावर पैक की स्थापना की लागत 50 डब्ल्यू पी और 150 डब्ल्यू पी पावर पैक की कुल स्थापना लागत से ₹ 11,048[12] प्रति यूनिट कम थी। इस प्रकार, कार्य के प्रारंभिक आवंटन (जुलाई/अगस्त 2018) के समय 200 डब्ल्यू पी पावर पैक का विकल्प नहीं चुनने के कारण, म.प्र.म.क्षे. वि.वि.कं.लि. को ₹ 0.46 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि सौर ऊर्जा पैक की क्षमता के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी, इसलिए, 50 डब्ल्यूपी पावर पैक स्थापित किया गया था और बाद में बैठक (जुलाई 2018) में चर्चा के उपरांत, 200 डब्ल्यूपी स्थापित किया गया था, तथा समय पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 150 डब्ल्यूपी के साथ 50 डब्ल्यूपी उन्नत किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सौभाग्य दिशानिर्देश (अक्टूबर 2017) में स्पष्ट रूप से 200-300 डब्ल्यूपी पावर पैक की स्थापना निर्धारित की गई थी।

[10] जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018 तक।

[11] अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019

[12] (₹ 17,622 + ₹ 24,774) - ₹ 31,348

3.3.7 योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार सामग्री उपलब्ध नहीं कराना

सौभाग्य दिशानिर्देशों के परिशिष्ट-V में कार्य के दायरे और सेवा कनेक्शन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के मानकों को निर्धारित किया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वितरण कंपनियाँ, सौभाग्य के तहत स्थापित विभिन्न सामग्रियों में मानकों का पालन करने में विफल रही है। इस संबंध में नीचे चर्चा की गई है:

- सौभाग्य के तहत घरेलू कनेक्शन में 4.0 मिमी^{2} आकार के ट्विन कोर (अकवचित) केबल प्रदान किए जाने का प्रावधान था । हालाँकि, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. की 12 नमूना[13] चयनित परियोजनाओं में 3,36,282 लाभार्थियों के लिए 2.5 मिमी^{2} आकार के घटिया ट्विन कोर (अकवचित) केबल स्थापित किए गए थे ।
- सौभाग्य के तहत घरेलू कनेक्शन में 40*3 मिमी एमएस फ्लैट क्लैंप के साथ 25 मिमी व्यास का जीआई पाइप प्रदान किया जाना था। हालाँकि, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. की चार नमूना चयनित परियोजनाओं[14] में 93,705 लाभार्थियों को 40*3 मिमी एमएस फ्लैट क्लैंप के साथ 20 मिमी व्यास (कम चौड़ाई) के जीआई पाइप स्थापित किए गए ।

परिणामस्वरूप, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सौभाग्य के तहत घरेलू कनेक्शन में निम्न मानकों वाली सामग्री प्रदान की गई, जिससे बुनियादी ढांचे की सेवा अवधि से समझौता हुआ ।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने कहा कि सौभाग्य के तहत निष्पादित कार्यों में वितरण कम्पनियों द्वारा अपने नियमित कार्यों के लिए अपनाए जाने वाले मानकों का पालन किया गया था ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वितरण कंपनियों ने योजना दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सामग्री के विनिर्देशों का पालन नहीं किया ।

3.3.8 सौर ऊर्जा पैक की स्थापना के लिए योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करना

- सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित अविद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों में सौर ऊर्जा पैक की स्थापना का प्रावधान किया गया है। घरों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने के लिए योजना के तहत बैटरी बैंकों के साथ 200 से 300 वाट पीक के बिजली पावर पैक प्रदान किए जाने थे। इसके अलावा, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, विद्युत की कुशल आपूर्ति के लिए पावर पैक की वाट पीक क्षमता को राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगशाला (एनआरईएल) के उपलब्ध सौर विकिरण डेटा के आधार पर वैश्विक क्षैतिज विकिरण (जीएचआई)[15] के रूप में माना जाएगा ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वैश्विक क्षैतिज विकिरण (जीएचआई) के प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश में, एनआरईएल द्वारा जारी भारत सौर संसाधन मानचित्र के आधार पर 250 डब्ल्यूपी का एक सौर ऊर्जा पैक प्रदान किया

[13] धार, झाबुआ, खरगोन, रतलाम, बैतूल, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला ।

[14] धार, झाबुआ, खरगोन, रतलाम ।

[15] <5 केडब्लूएच/एम2 /दिन के जीएचआई वाले क्षेत्रों के लिए 300 डब्ल्यूपी, >5 से 5.5 केडब्लूएच/एम2 /दिन के GHI वाले क्षेत्रों के लिए 250 डब्ल्यूपी और > 5.5 केडब्लूएच/एम2 /दिन के जीएचआई वाले क्षेत्रों के लिए 200 डब्ल्यूपी ।

जाना था। इसके बावजूद, वितरण कम्पनियों ने ₹ 10.26 करोड़ के 200 वाट पीक (डब्ल्यूपी) के 2,964 सौर ऊर्जा पैक स्थापित किए **(परिशिष्ट 3.3)** जिसके परिणामस्वरूप, घरों को योजना की परिकल्पना से कम बिजली की आपूर्ति की गई।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने टिप्पणी को स्वीकार किया और उसका संज्ञान लिया।

- योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि सौभाग्य के तहत स्वीकृत कार्यों को वितरण कम्पनियों द्वारा ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. की रतलाम और रायसेन परियोजना ने ₹ 1.86 करोड़ के 484[16] सौर ऊर्जा पैक की आपूर्ति और स्थापना के लिए ई-टेंडर के बजाय कोटेशन आमंत्रण नोटिस जारी किया।
- इसके अलावा, सौभाग्य दिशानिर्देशों के अध्याय-II परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन की कंडिका 2.6 में ऑफ-ग्रिड कनेक्शन के लिए स्थापित उपकरणों के पांच साल के संधारण और रखरखाव का प्रावधान निर्धारित किया गया है। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वितरण कम्पनियों की दो परियोजनाओं[17] में बिना औचित्य बताए संधारण और रखरखाव के पांच वर्षों के प्रावधानों के बजाय 12/18 माह के संधारण और रखरखाव प्रावधान को कार्यादेश में शामिल किया गया।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने आश्वासन दिया कि इस प्रकरण का अवलोकन टिप्पणी को देखते हुए किया जाएगा और वितरण कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में इसी तरह की घटनाएं न हों।

3.3.9 गलत आधार पर नकद पुरस्कार की प्राप्ति

ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.म.), भारत सरकार ने सौभाग्य में वितरण कम्पनी के स्तर पर 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के लिए नकद पुरस्कार योजना शुरू की (24 अक्टूबर 2018)। इस उद्देश्य के लिए राज्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था (i) विशेष (ii) विशेष के अलावा अन्य (5 लाख से कम अविद्युतीकृत घरों) और (iii) विशेष के अलावा अन्य (5 लाख से अधिक घरों)। प्रत्येक श्रेणी में, 30 नवंबर 2018 तक 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाली पहली वितरण कम्पनी को ₹ 100 करोड़ का नकद पुरस्कार वितरित किया जाना था। इसके अलावा, वितरण कम्पनियों के कर्मचारियों के बीच ₹ 0.50 करोड़ का नकद पुरस्कार भी वितरित किया जाना था। राज्य की तीन वितरण कम्पनियों में से दो वितरण कम्पनियों, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.प.क्षे. वि.वि.कं.लि. प्रत्येक को ₹ 100.50 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार मिला। लेखापरीक्षा ने पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता की समीक्षा की और निम्नलिखित कमियाँ पाई :

- म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को 5 लाख से अधिक गैर-विद्युतीकृत घरों के साथ श्रेणी (iii) के तहत वर्गीकृत किया गया था और 30 सितंबर 2018 तक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की उपलब्धि के प्रमाण पत्र के आधार पर ₹ 100.50 करोड़ का नकद पुरस्कार प्राप्त किया (26 फरवरी 2019)। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. की पांच नमूना चयनित परियोजनाओं[18] में से दो में, दिसंबर 2018 के बाद 4,725 घरों के विद्युतीकरण के लिए 24 कार्यादेश जारी किए गए थे और जनवरी 2019 से अक्टूबर

[16] रतलाम में 70 की संख्या ₹ 0.10 करोड़ में एवं रायसेन में 414 की संख्या ₹ 1.76 करोड़ में।

[17] म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. का रतलाम (12 माह) और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. का रायसेन (18 माह)।

[18] विदिशा और राजगढ़।

2019 के दौरान पूरे किए गए थे। इसलिए, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. का सितंबर 2018 तक पूर्ण विद्युतीकरण का दावा गलत था।

- इसी प्रकार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. को 5 लाख से कम गैर-विद्युतीकृत घरों वाले (ii) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 28 जुलाई 2018 तक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की उपलब्धि के प्रमाण पत्र के आधार पर ₹ 100.50 करोड़ का नकद पुरस्कार प्राप्त किया (26 फरवरी 2019)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. की चार नमूना चयनित परियोजनाओं[19] में 8,985 कनेक्शन जारी करने के लिए 32 कार्यदेश दिसंबर 2018 के बाद जारी किए गए थे और फरवरी 2019 से जून 2019 के दौरान पूरे किए गए थे। इसलिए, जुलाई 2018 तक पूर्ण विद्युतीकरण का म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. का दावा गलत था।

इस प्रकार, आरईसी के समक्ष सौभाग्य के तहत 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण की गलत घोषणा के कारण ₹ 201.00 करोड़ का अयोग्य पुरस्कार प्राप्त हुआ।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने स्वीकार किया कि 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा के बाद घरों में कुछ कनेक्शन प्रदान किए गए थे क्योंकि वितरण कम्पनियों ने 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण की घोषणा के बाद असंबद्ध और इच्छुक घरों, यदि कोई हो, को कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था।

हालाँकि, तथ्य यह है कि यद्यपि योजना के तहत 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण प्रमाणित किया गया था, 31 दिसंबर 2018 तक घरों का विद्युतीकरण लंबित था।

3.3.10 गलत आधार पर अतिरिक्त अनुदान की प्राप्ति

सौभाग्य दिशानिर्देशों के अध्याय II (परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन) की कंडिका 9 में कहा गया है कि वितरण कम्पनियों को 31 मार्च 2019 तक घरेलू विद्युतीकरण का कार्य पूरा करना होगा। हालाँकि, परियोजना की कुल लागत का 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान 31 दिसंबर 2018 तक 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण की उपलब्धि पर ही जारी किया जाना था। काम जल्दी पूरा करने के लिए तीनों वितरण कम्पनियों हेतु आरईसी द्वारा ₹ 110.54 करोड़[20] का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया गया (29 सितंबर 2021)। अनुदान राशि में से मार्च 2022 तक ₹ 49.53 करोड़[21] प्राप्त हो चुके थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के क्रमशः 4,725, 8,985 और 37,834 घरों के विद्युतीकरण का कार्य 31 दिसंबर 2018 तक लंबित था। इस प्रकार, अतिरिक्त अनुदान के लिए किए गए दावे संबंधित वितरण कम्पनियों द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने इसे स्वीकारा कि 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा के बाद कुछ घरों को कनेक्शन प्रदान किए गए क्योंकि वितरण कम्पनियों ने 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण की घोषणा के बाद, कनेक्शन से असंबद्ध और इच्छुक घरों, को कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था।

---

[19] धार, झाबुआ, खरगोन, रतलाम।

[20] म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. -₹ 38.76 करोड़, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. -₹ 17.60 करोड़ और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. -₹ 54.18 करोड़

[21] म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. -₹ 22.62 करोड़, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. -₹ 12.79 करोड़ और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. -₹ 14.12 करोड़

हालाँकि, तथ्य यह है कि यद्यपि योजना के तहत 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण प्रमाणित किया गया था, 31 दिसंबर 2018 तक घरों का विद्युतीकरण लंबित था।

3.3.11 आरईसी गुणवत्ता निगरानीकर्ता के प्रतिवेदन का पालन न करना

गुणवत्ता निगरानी पर सौभाग्य दिशानिर्देश में निर्धारित किया गया है कि आरईसी, गुणवत्ता निगरानीकर्ता (आर.क्यू.एम.) की नियुक्ति के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन करेगा। तदनुसार, आर.क्यू.एम. ने 13 नमूना चयनित परियोजनाओं के 715 गांवों का भौतिक सत्यापन किया।

लेखापरीक्षा ने 27 मई 2019 से 22 दिसंबर 2020 तक जारी आर.क्यू.एम. के प्रतिवेदन की जांच की और पाया कि आर.क्यू.एम. ने घरों के विद्युतीकरण और बुनियादी ढांचे (एचटी लाइन, एलटी लाइन, डीटीआर, एचटी पोल, एलटी पोल) के कार्य में कम निष्पादन पाया, जिसे नीचे **तालिका 3.7** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.7: योजनांतर्गत कम निष्पादन का विवरण

क्र. सं.	वितरण कम्पनी का नाम	निरीक्षण किए गए गावों की संख्या	घरों और बुनियादी ढांचे के विद्युतीकरण के संक्षिप्त निष्पादन का विवरण						
			बीपीएल (संख्या में)	एपीएल (संख्या में)	एचटी लाइन (सीकेएम में)	एचटी पोल (संख्या में)	एलटी लाइन (सीकेएम में)	एलटी पोल (संख्या में)	डी टी आर (संख्या में)
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	283	2,349	1,262	35	530	36	606	19
2.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	214	3,567	101	178	1,022	846	1,766	107
3.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	218	3,142	56	83	860	115	1,778	73
	कुल	**715**	**9,058**	**1,419**	**295**	**2,412**	**997**	**4,150**	**199**

*(**स्रोत**: साक्ष्य पोर्टल से प्राप्त आर.क्यू.एम. निरीक्षण प्रतिवेदन)*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि आरईसी ने वितरण कम्पनियों की समापन प्रतिवेदन को मंजूरी[22] दे दी थी, लेकिन वितरण कम्पनियों ने उन कार्यों के समायोजन के लिए आरईसी से संपर्क नहीं किया, जिन्हें आर.क्यू.एम. द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन में अल्प निष्पादित घोषित किया गया था।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि आर.क्यू.एम. ने बुनियादी ढांचे में अंतर को इंगित किया था, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई/ अगस्त 2023) कि अनुपालन प्रतिवेदन आरईसी को प्रस्तुत कर दिया गया था।

हालाँकि, वितरण कम्पनियों ने प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन और आरईसी द्वारा इसकी स्वीकृति के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए।

निष्कर्ष: वितरण कम्पनियों ने निविदा प्रक्रिया में योजना दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और मानकों एवं कार्य की वास्तविक आवश्यकताओं के विपरीत सामग्री खरीदी गई। साथ ही, वितरण कम्पनियों द्वारा गांवों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के संबंध में असत्य घोषणा की गई। वितरण कम्पनियों द्वारा आरईसी द्वारा बताई गई कमियों को भी सुधारा नहीं गया।

अनुशंसा: वितरण कम्पनियों को निविदा प्रक्रिया में योजना दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए और सामग्रियों का क्रय मानकों एवं कार्य की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार करके किया जाना चाहिए।

[22] 29 सितंबर 2021

वितरण कम्पनियों को विद्युतीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति पर असत्य घोषणाएं दर्ज करने से बचना चाहिए और वितरण कम्पनियों को आरईसी के साथ कमियों का समायोजन करना चाहिए।

3.4 परियोजनाओं का समापन एवं अनुमोदन

योजना दिशानिर्देशों के अध्याय-V के कंडिका 10.1 के अनुसार, अंतिम किश्त आरईसी को समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद जारी की जानी थी। समापन प्रतिवेदन परियोजना पूरा होने की तारीख से एक साल के भीतर जमा करनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वितरण कम्पनियों ने आरईसी को समापन प्रतिवेदन 490/492 दिनों की देरी से सौंपे, जैसा कि नीचे **तालिका 3.8** में दिया गया है:

तालिका 3.8: समापन प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण मे देरी का विवरण

क्र.सं.	वितरण कम्पनी का नाम	परियोजनाओं की संख्या	दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना पूर्ण होने की तिथि	समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की लक्ष्य तिथि	वास्तविक परियोजना पूर्ण होने की तिथि	समापन प्रतिवेदन जमा करने की वास्तविक तारीख	समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	16	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	03.08.2021	490
2.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	14	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	05.08.2021	492
3.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	20	31.03.2019	31.03.2020	18.03.2019	05.08.2021	492

*(**स्रोत:** वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)*

इस प्रकार, वितरण कम्पनियों ने परियोजनाओं की समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में 490 से 492 दिनों तक की देरी की। परिणामस्वरूप, समापन प्रतिवेदन की मंजूरी में भी देरी हुई और इसे सितंबर 2021 में ही प्राप्त किया जा सका। इससे ₹ 263.41 करोड़ रुपये की अंतिम किस्त जारी करने में भी देरी हुई। इसके अलावा, 31 मार्च 2022 तक आरईसी द्वारा ₹ 61.01 करोड़ जारी करना अभी भी लंबित था।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई/अगस्त 2023) कि आरईसी द्वारा अंतिम संशोधित समापन प्रतिवेदन प्रारूप नवंबर/दिसम्बर 2020 में प्रदान किया गया है और समापन प्रतिवेदन लक्ष्य तिथि से अर्थात 10 अगस्त 2021 से काफी पहले 03/05 अगस्त 2021 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में योजना दिशानिर्देशों की तुलना में असामान्य देरी हुई थी।

3.4.1 निष्पादित मात्रा की तुलना में अधिक लाभार्थियों का दावा

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समापन प्रतिवेदन में दावा किए गए लाभार्थियों की संख्या सौभाग्य में लाभार्थियों को कनेक्शन प्रदान करने के निष्पादित आकड़ों से अधिक थी जैसा कि नीचे **तालिका 3.9** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 3.9: लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	वितरण कम्पनी का नाम	परियोजनाओं का नाम	उन लाभार्थियों की संख्या जिनके कनेक्शन निष्पादन के अनुसार जारी किए गए थे	समापन प्रतिवेदन में दावा किए गए लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की अधिक संख्या का दावा
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	भोपाल	7,139	16,550	9,411
2.		विदिशा	37,103	48,724	11,621
3.		रायसेन	41,040	46,752	5,712
4.		राजगढ़	53,631	62,478	8,847
5.		बैतूल	29,797	32,264	2,467
6.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	धार	11,010	17,542	6,532
7.		झाबुआ	24,276	34,595	10,319
8.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बालाघाट	34,995	44,871	9,876
9.		शहडोल	31,437	44,061	12,624
10.		मंडला	34,179	36,202	2,023
11.		डिंडौरी	25,617	31,761	6,144
कुल			**3,30,224**	**4,15,800**	**85,576**

*(**स्रोत**: वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)*

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि 11[23] नमूना चयनित परियोजनाओं में वितरण कम्पनियों ने 3,30,224 लाभार्थियों को कनेक्शन प्रदान किए थे, लेकिन आरईसी को सौंपे गए समापन प्रतिवेदन में 4,15,800 लाभार्थियों के दावे दर्ज किए थे। इस प्रकार, आरईसी के समक्ष 11 नमूना चयनित परियोजनाओं में 85,576 लाभार्थियों के लिए ₹ 24.06 करोड़ का अतिरिक्त दावा किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और संज्ञान लिया।

निष्कर्ष: वितरण कम्पनियों ने देरी से और अतिरिक्त दावे के साथ समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

अनुशंसा: वितरण कम्पनियों को समयसीमा का पालन करते हुए सही दावा प्रस्तुत करना चाहिए।

3.5 वित्तीय प्रबंधन

सौभाग्य योजनांतर्गत निधि दिशानिर्देशों के अध्याय V की कंडिका 1.1 मे निधि व्यवस्था और वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है जैसा कि नीचे **तालिका 3.10** में दर्शाया गया है:

[23] दो परियोजनाओं (खरगोन और रतलाम) में आवंटन की सारांशित सूची उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण घरेलू कनेक्शन के निष्पादित आंकड़ों की तुलना समापन प्रतिवेदन आंकड़ों से नहीं की जा सकी।

तालिका 3.10: सौभाग्य योजनांतर्गत निधि व्यवस्था

क्र.सं.	एजेंसी	सहयोग की प्रकृति	सहयोग की मात्रा (परियोजना लागत का प्रतिशत)
1.	भारत सरकार	अनुदान	60
2.	राज्य/वितरण कम्पनिया/उपयोगिता योगदान	स्वयं का कोष	10
3.	ऋणदाता (एफआई/बैंक)	ऋण	30
4.	निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण घटक का 50 प्रतिशत (30 प्रतिशत) अर्थात 15 प्रतिशत

***(स्रोत:** सौभाग्य योजना दिशानिर्देश।)*

लेखापरीक्षा ने निधि दिशानिर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की और निधि दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के प्रकरण पाए जैसा कि आगामी **कंडिका 3.5.1 और 3.5.2 में** चर्चा की गई है।

3.5.1 'स्वयं निधि' के हिस्से के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने में विफलता

सौभाग्य के कंडिका 1.1 में यह निर्धारित किया गया है कि वितरण कम्पनियों को योजना में कुल स्वीकृत लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा 'स्वयं निधि' के रूप में प्रदान करना चाहिए, जिसकी व्यवस्था उसे अपने स्रोत या सरकारी सहायता के माध्यम से करना चाहिए।

म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में सौभाग्य योजना के तहत ₹ 989.30 करोड़ रुपये की कुल लागत से 20 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। 'स्वयं निधि' के योगदान की व्यवस्था करने के लिए जो स्वीकृत लागत का 10 प्रतिशत है, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने म.प्र. शासन से संपर्क किया (27 जुलाई 2018) और म.प्र. शासन ने इसे प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी (20 अगस्त 2018)। म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने 30 प्रतिशत की तुलना में ₹ 395.72 करोड़[24] के ऋण के रूप में स्वीकृत लागत के 40 प्रतिशत के लिए आरईसी से संपर्क किया और आरईसी ने इसे मंजूरी दी (10 सितंबर 2018)। लेखापरीक्षा ने पाया कि म.प्र. शासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने म.प्र. शासन से 10 प्रतिशत हासिल करने के बजाय, 'स्वयं के फंड' के लिए आरईसी से 10 प्रतिशत ऋण लिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने म.प्र. शासन से 10 प्रतिशत का 'स्वयं निधि' अंशदान मांगा और प्राप्त किया।

इस प्रकार, स्वीकृत लागत के 40 प्रतिशत पर ऋण प्राप्त करना योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था जिसने इसे 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। परिणामस्वरूप, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. को मार्च 2022 तक ₹ 98.93 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लेना पड़ा और ₹ 24.65 करोड़ का परिहार्य ब्याज उठाना पड़ा।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने बताया कि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने राशि मांगी थी, लेकिन म.प्र. शासन ने इसे जारी नहीं किया।

[24] ₹ 989.30 X 40 प्रतिशत।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि म.प्र. शासन ने स्वीकृत लागत का 10 प्रतिशत वित्त पोषण करने की मंजूरी दे दी (20 अगस्त 2018) थी । म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. की तरह म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. इसका लाभ नहीं उठा सकी।

3.5.2 दोषपूर्ण ऋण व्यवस्था के कारण अतिरिक्त शुल्क का परिहार्य भुगतान

सौभाग्य के कार्यान्वयन के लिए वितरण कम्पनियों ने आरईसी के साथ एक ऋण समझौता किया (मार्च 2019)। ऋण समझौते के नियमों और शर्तों में यह निर्धारित था कि सौभाग्य में परियोजना लागत के अनुरूप सावधि ऋण की मूल राशि, ब्याज और अन्य शुल्कों को भविष्य की सभी चल संपत्तियों, सामग्री के भंडार, स्थापित उपकरणों को दृष्टिबंधक रखकर एक विशेष प्रथम अधिकार के माध्यम से सुरक्षित की जाएगी । इसके अलावा, राज्य सरकार की गारंटी नहीं मिलने पर 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाने का भी प्रावधान था। हालाँकि, आरईसी (09 नवंबर 2018) ने सौभाग्य के कार्यान्वयन के लिए उधार लिए गए ऋण पर मौजूदा परिसंपत्तियों के 30 प्रतिशत का बंधक/ गिरवी जमा करने के बदले में सरकारी गारंटी जमा करने की शर्त को हटा दिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने छूट की इस शर्त का लाभ उठाया और छूट के नियमों और शर्तों के अनुसार संपत्तियों को गिरवी रख दिया, जबकि म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने किसी भी अभिलिखित औचित्य के बिना अतिरिक्त संपत्तियों को गिरवी रखकर छूट की वैकल्पिक शर्त का लाभ नहीं उठाया। नतीजतन, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने सौभाग्य के कार्यान्वयन के लिए उधार लिए गए ऋण के लिए मार्च 2022 तक ₹ 0.72 करोड़[25] का अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया।

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई/अगस्त 2023) कि सौभाग्य के तहत बनाई गई संपत्ति आरईसी के पास गिरवी थी और गारंटी प्रदान करने के लिए म.प्र. शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. के विपरीत, मौजूदा परिसंपत्तियों का 30 प्रतिशत गिरवी नहीं रखा।

निष्कर्ष: म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. अपने स्वयं के निधि के हिस्से के लिए म.प्र. शासन से धन प्राप्त करने में विफल रहा एवं म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ऋण समझौते की अनुकूल शर्तों का लाभ उठाने में विफल रहे।

अनुशंसा: म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. को अपने स्वयं के निधि के हिस्से के लिए म.प्र. शासन से धन प्राप्त करना चाहिए एवं म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को ऋण समझौते की अनुकूल शर्तों का लाभ उठाना चाहिए।

3.6 निगरानी प्रबंधन

योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, वितरण कम्पनियों को योजना के गुणवत्ता निगरानी दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक था। साथ ही, सौभाग्य कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वितरण कंपनियाँ पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह होंगी । तदनुसार, वितरण कंपनिया सौभाग्य कार्यों के तहत गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के

[25] म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. -₹ 0.72 करोड़, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने अतिरिक्त शुल्क का विवरण नहीं दिया।

निर्माण के लिए एक व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यू.ए.) और निरीक्षण योजना तैयार करेगी। क्यूए और निरीक्षण योजना आंशिक टर्नकी और कार्यों के विभागीय निष्पादन के मामले में, जैसा भी मामला हो, टर्नकी ठेकेदार या उपकरण आपूर्तिकर्ता/विक्रेता और निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध समझौते का एक अभिन्न अंग होगा। वितरण कम्पनियों को यह सुनिश्चित करना था कि साइट पर आपूर्ति की गई सामग्री/उपकरण की गुणवत्ता और परियोजना के तहत कार्यों का निष्पादन क्यू.ए. और निरीक्षण योजना के अनुसार हो।

लेखापरीक्षा ने योजना में निर्धारित निगरानी दिशानिर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी.एम.ए.) की नियुक्ति न होना तथा आकणों का अनुचित रख-रखाव आदि, कमियां पाई। जिसकी चर्चा आगामी **कंडिका 3.6.1** में की गई है।

गुणवत्ता संबंधी समस्याएं

3.6.1 परियोजनाओं की निगरानी में कमियाँ

दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर योजना की निगरानी के लिए विभिन्न प्राधिकरण स्थापित किए गए थे, जैसे:

- राज्य स्तरीय स्थायी समिति[26] प्रगति की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और समापन प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के साथ-साथ स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को हल करेगी।
- परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियाँ (दिशा)।
- परियोजना प्रबंधन और इसके कार्यान्वयन में वितरण कम्पनियों की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी.एम.ए.) की नियुक्ति।

लेखापरीक्षा ने इन प्राधिकरणों द्वारा निगरानी पर निम्नलिखित अवलोकन बिन्दु पाए जैसा **तालिका 3.11 में** संक्षेप में दिया गया है:

तालिका 3.11: लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

क्र.सं.	निगरानी स्तर	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	**राज्य स्तरीय स्थायी समिति** सौभाग्य के लिए मई 2018 में इसका गठन किया गया था। राज्य स्तरीय स्थायी समिति आरईसी को डीपीआर की सिफारिश करने, परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने, गुणवत्ता नियंत्रण और समापन प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार थी।	➢ समिति के गठन का आदेश बैठकें की आवृत्ति पर मौन था जिस पर समिति को बैठकें बुलाई जानी थीं। इस प्रकार, राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक केवल दो बार (मार्च 2018 और मई 2019) हुई। डीपीआर को मंजूरी देने के लिए बैठकें आयोजित की गईं। ➢ वितरण कम्पनियों ने राज्य स्तरीय स्थायी समिति को बताया कि विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, हालांकि, वितरण कम्पनियों ने विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं किया और इसे राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। ➢ राज्य स्तरीय स्थायी समिति ने योजना में आवश्यक भागीदारी के लिए अपने स्वयं के योगदान के लिए निधि की व्यवस्था करने के संबंध में म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. कं.लि. के विचलन पर चर्चा नहीं की। ➢ राज्य स्तरीय स्थायी समिति ने कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान, समय पर अंतिम रूप देने और समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदि की निगरानी नहीं की। जिसमें कुछ

[26] राज्य स्तरीय स्थायी समिति में मुख्य सचिव (अध्यक्ष के रूप में), ऊर्जा, वित्त, राजस्व, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और गृह विभाग के सचिव, मुख्य महाप्रबंधक (आरईसी) और तीन वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक शामिल हैं।

क्र.सं.	निगरानी स्तर	लेखापरीक्षा अवलोकन
		कमियां थीं जो इस प्रतिवेदन के **कंडिका 3.3, 3.4 और 3.6** में बताई गई हैं। शासन ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया (अगस्त 2023)।
2.	**जिला स्तर पर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समितियाँ** जिला स्तर पर, जिले में चल रही परियोजनाओं के लिए दिशा समितियों[27] का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष जिले के एक सांसद को बनाया गया था, इन समितियों को परियोजनाओं के निर्माण से लेकर कार्यान्वयन और निगरानी तक शामिल किया जाना था।	➢ दिशा डीपीआर के निर्माण में शामिल नहीं थी। ➢ दिशा को जिला स्तर पर कम से कम हर तिमाही बैठक करना आवश्यक था। अक्टूबर 2017 से मार्च 2019[28] के दौरान, यह देखा गया कि संबंधित वितरण कम्पनियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले चयनित तेरह जिलों में आयोजित होने के लिए आवश्यक 78 बैठकों के मुकाबले कुल 14 बैठकें ही आयोजित की गईं। ➢ दिशा में सौभाग्य के तहत निष्पादित कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता आश्वासन पर चर्चा नहीं की गई। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वितरण कम्पनियों द्वारा प्रगति पर बैठकें आयोजित करने और चर्चा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि दिशा ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.म.) दिशानिर्देशों के अनुसार सौभाग्य का हिस्सा नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सौभाग्य दिशानिर्देशों के अध्याय IV के कंडिका 1 में यह निर्धारित किया गया है कि डीडीयूजीजेवाई में अपनाए गए निगरानी तंत्र का सौभाग्य में भी पालन किया जाएगा।
3.	**परियोजना प्रबंधन एजेंसी** निगरानी, गुणवत्ता आश्वासन और सौभाग्य दिशानिर्देशों के मूल्यांकन के अध्याय IV के कंडिका 1 में यह निर्धारित किया गया है कि डीडीयूजीजेवाई में अपनाई गई निगरानी प्रणाली का सौभाग्य में भी पालन किया जाएगा। इस संबंध में, परियोजना निर्माण और डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के कंडिका 11 में प्रावधान है कि परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी.एम.ए.) को वितरण कम्पनियों द्वारा परियोजना प्रबंधन में सहायता करने और परियोजना के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। पी.एम.ए. पर किए गए व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा सौ प्रतिशत अनुदान (कार्य की लागत का 0.5 प्रतिशत तक) प्रदान किया जाना था। वितरण कंपनियाँ नामांकन के आधार पर या खुली बोली के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) के पूल से पी.एम.ए. का चयन कर सकती हैं। दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि बोली प्रक्रिया, परियोजना योजना और कार्यान्वयन, गुणवत्ता निगरानी, एमआईएस और वेब पोर्टल	➢ म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने पी.एम.ए. की नियुक्ति नहीं की और इसके परिणामस्वरूप सौभाग्य परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे वि.परि.प्रति.की तैयारी और अपलोडिंग में सहायता, अनुबंध देने, निगरानी, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण परामर्श आदि से संबंधित गतिविधियां पी.एम.ए. के माध्यम से नहीं की गईं। लेखापरीक्षा को पी.एम.ए. की नियुक्ति न करने का कोई औचित्य दर्ज नहीं मिला। पी.एम.ए. की नियुक्ति न होने से योजना की शर्तों का उल्लंघन हुआ और ₹ 347.77 करोड़ की लागत से निष्पादित नौ नमूना चयनित परियोजनाओं[29] में खराब निगरानी हुई। निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने कहा कि सौभाग्य में म.प्र.म.क्षे. वि.वि.कं.लि. और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा पी.एम.ए. की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसके बजाय, परियोजना की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भर्ती किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियोंको परियोजना प्रबंधन में सहायता करने और योजना दिशानिर्देशों के तहत परियोजना के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पी.एम.ए. नियुक्त करने की आवश्यकता थी। ➢ सौभाग्य के तहत, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने डीडीयूजीजेवाई ठेकेदारों और नए आवंटन के माध्यम से निष्पादित परियोजनाओं के लिए डीडीयूजीजेवाई के पी.एम.ए. के मौजूदा अनुबंध को बढ़ाकर देर से (25 फरवरी 2019) पी.एम.ए. नियुक्त किया। ये कार्य 31 मार्च 2019 तक पूरे हो गए। ऐसे में, पी.एम.ए. सेवा का विस्तार अप्रासंगिक था क्योंकि योजना के तहत परियोजनाएं अक्टूबर 2017 से शुरू हुईं और पी.एम.ए. को शुरू से ही कार्यों की निगरानी करनी थी। इस प्रकार, सौभाग्य कार्यों के निष्पादन की निगरानी के लिए चयनित चार परियोजनाओं[30] में पी.एम.ए. को भुगतान की गई ₹ 0.50 करोड़[31] की राशि निरर्थक थी। इसके अलावा, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने विभागीय रूप से निष्पादित कार्यों और आरजीजीवीवाई कार्यों के विस्तार के लिए

[27] सदस्यों में शामिल हैं, अर्थात जिला कलेक्टर/जिला आयुक्त, जिले से राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, सभी नगर पालिकाओं के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदि।

[28] परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि।

[29] भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, बैतूल, शहडोल, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट।

[30] धार, झाबुआ, खरगोन एवं रतलाम।

[31] धार - ₹ 0.19 करोड़ + झाबुआ - ₹ 0.14 करोड़ + खरगोन - ₹ 0.06 करोड़ + रतलाम - ₹ 0.11 करोड़।

क्र.सं.	निगरानी स्तर	लेखापरीक्षा अवलोकन
	को अद्यतन करने की निगरानी और समन्वय अनिवार्य रूप से पी.एम.ए. को सौंपा जाना चाहिए।	₹ 52.43 करोड़ (कुल परियोजनाओं की लागत ₹ 147.98 करोड़ का 35.43 प्रतिशत) के लिए पी.एम.ए. को नियुक्त नहीं किया। इस प्रकार, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. द्वारा पी.एम.ए. सेवा का प्रभावी ढंग से लाभ नहीं उठाया गया। म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि भले ही पी.एम.ए. की नियुक्ति देर से की गई थी, लेकिन पी.एम.ए. की सेवाएं यथावत बनी रहीं क्योंकि डीडीयूजीजेवाई आवंटन को सौभाग्य के लिए बढ़ा दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि पी.एम.ए. ने सौभाग्य कार्यों की निगरानी की थी और पी.एम.ए. को परियोजना के पूर्ण होने के चरण में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा विभागीय तौर पर और आरजीजीवीवाई कार्यों के विस्तार के माध्यम से निष्पादित परियोजनाओं के मामले में पी.एम.ए. की नियुक्ति नहीं की गई थी।

***(स्रोत**: सौभाग्य दिशानिर्देश और जानकारी, जैसा कि वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान किया गया और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित किया गया है)*

3.6.2 आरईसी गुणवत्ता निगरानीकर्ता द्वारा बताई गई खामियों को ठीक न किया जाना

गुणवत्ता निगरानी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आरईसी ने सौभाग्य के तहत किए गए कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आरईसी गुणवत्ता निगरानीकर्ता (आर.क्यू.एम.) नियुक्त किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आर.क्यू.एम. ने 13 नमूना चयनित परियोजनाओं में 715 गांवों में 17,101 दोष (4,208 महत्वपूर्ण, 11,172 बड़े और 1,721 छोटे दोष) बताए[32]। हालाँकि, योजना के पूरा होने के 42 महीने (प्रतिवेदन जारी होने से 21 महीने) बीत जाने के बावजूद, 488 गाँवों में 6,584 दोष (1,658 महत्वपूर्ण, 4,314 बड़े और 612 छोटे दोष) अभी तक ठीक नहीं किए गए (सितंबर 2022)। इन दोषों के लंबित रहने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, आर.क्यू.एम. द्वारा इंगित बड़ी संख्या में दोष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि आर.क्यू.एम. द्वारा बताए गए दोषों की सीमा तक घटिया कार्य योजना के गुणवत्ता निगरानी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निष्पादित किए गए थे। इसके अलावा, चूंकि संबंधित वितरण कम्पनियों द्वारा अभी तक दोषों को ठीक नहीं किया गया है, इसलिए बनाए गए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता घटिया बनी हुई है।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने बताया कि वितरण कम्पनियों द्वारा दोषों को ठीक कर लिया गया था और आरईसी के साथ उनका समायोजन कर दिया गया था और प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाएंगे।

सुधार की स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि वितरण कम्पनियों ने संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे।

3.6.3 डैशबोर्ड और वितरण कम्पनियों के रिकॉर्ड के अनुसार विभिन्न घटकों में अंतर

सौभाग्य के कार्यान्वयन की प्रगति वितरण कम्पनियों द्वारा अद्यतन/प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.म.) के डैशबोर्ड में परिलक्षित हो रही थी। वितरण कम्पनियों के सौभाग्य के तहत सभी कार्य मार्च 2019 तक पूर्ण हो चुके थे। इस प्रकार, समापन प्रतिवेदन के अनुसार कार्यों की प्रगति ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.म.) के पोर्टल पर दिखाई जानी चाहिए थी।

[32] निरीक्षण रिपोर्ट आरईसी साक्ष्य पोर्टल से ली गई है।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डैशबोर्ड और समापन प्रतिवेदन में दर्शाई गई प्रगति (मार्च 2019) में भिन्नताएँ थीं, जैसा कि नीचे **तालिका 3.12** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 3.12: डैशबोर्ड और समापन प्रतिवेदन में भिन्नताएँ

क्र.सं.	विभिन्न घटकों के नाम	भिन्नता (सीमा में)		
		म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
1.	लाभार्थी (संख्या)	4807 to 7,209	(-486) to 34,536	(-2,731) to (-2,228)
2.	डीटीआर (संख्या)	7 to 66	(-76) to 198	(-391) to 147
3.	11 केवी लाइन (सीकेएम)	(-9) to 65	(-184) to 343	120 to 124

***(स्रोत:** डैशबोर्ड पर परिलक्षित प्रगति प्रतिवेदन और वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और ऑडिट द्वारा संकलित)*

उपरोक्त भिन्नताएँ सौभाग्य के कार्यान्वयन के दौरान पर्याप्त एमआईएस संधारण में वितरण कम्पनियों की विफलता को दर्शाती हैं।

निर्गम सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने टिप्पणी को स्वीकार किया और संज्ञान लिया।

निष्कर्ष: म.प्र. शासन और वितरण कम्पनियाँ योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र सुनिश्चित नहीं कर सकीं, परिणामस्वरूप, वितरण कम्पनियों द्वारा निष्पादित कार्यों पर आर.क्यू.एम. द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में बड़ी संख्या में विसंगतियां थीं और समापन प्रतिवेदन की तुलना में डैशबोर्ड में दर्शाए गए आंकड़ों में कई विसंगतियां थीं।

अनुशंसा: म.प्र.शासन और वितरण कम्पनियों को योजना दिशानिर्देशों के पालन में गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन और परियोजना निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

अध्याय-IV

अध्याय-IV

लाभार्थी का सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा ने अगस्त-सितंबर 2021 में डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के लाभार्थियों के साथ क्षेत्र में सर्वेक्षण किया। लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए 13 नमूना चयनित जिलों में से 30 ब्लॉकों और प्रत्येक ब्लॉक से पांच गांवों का चयन किया गया। प्रत्येक गांव में, सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों की वास्तविक संख्या सर्वेक्षण के लिए चयनित 10 की अधिकतम संख्या हो सकती थी। इस प्रकार, 13 नमूना चयनित जिलों के 150 गांवों में डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के कुल 1,185 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया। प्रश्नावली का प्रारूप **परिशिष्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

तीन वितरण कंपनियों में सर्वेक्षण किए गए इन 1185 लाभार्थियों/परिवारों (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-406, म.प्र.प.क्षे. वि.वि.क.लि.-406 और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.-373) पर आधारित लेखापरीक्षा प्रेक्षण नीचे दिए गए हैं :

(1) तकनीकी विशिष्टताओं और निर्माण मानकों के अनुरूप सिंगल-पॉइंट वायरिंग, एलईडी लैंप और सहायक उपकरण का प्रावधान न करना

सौभाग्य दिशानिर्देशों के कंडिका 2.4 के अनुसार, विद्युत कनेक्शन में ऊर्जा मीटर और एलईडी लैंप की स्थापना का प्रावधान शामिल था।

सर्वेक्षण के अनुसार, 54 लाभार्थियों/परिवारों के मामले में (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.-23, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-26, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.-5) ऊर्जा मीटर उपलब्ध नहीं कराए गए थे और 332 लाभार्थियों/परिवारों के मामले में, (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.-102, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-98, म.प्र.पू.क्षे.वि. वि.क.लि.-132) एलईडी लैंप प्रदान नहीं किए गए थे।

(2) सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को भुगतान पर विद्युत कनेक्शन जारी करना

सौभाग्य दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) आंकड़ो के अनुसार शामिल किए गए लाभार्थियों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना था। सर्वेक्षण में शामिल परिवारों ने उद्घाटित खुलासा किया कि उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 13 (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.-2, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-2, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.-9) परिवारों के मामले में, दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए भुगतान लेने के बाद कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

(3) मासिक व्यय पर प्रभाव

158 लाभार्थियों/परिवारों (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.-61, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-97, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. क.लि.-0) ने बताया कि डीजल जेन-सेट, डीजल पंप आदि के कम उपयोग के कारण मासिक व्यय में कमी आई है।

(4) घर में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उपयोग

831 लाभार्थियों/परिवारों (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.-227, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-373, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. क.लि.-231) ने बताया कि विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के बाद, वे टीवी, फ्रिज, पंखे आदि जैसे अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग कर रहे थे।

(5) घर में विद्युत कनेक्शन से पहले और बाद में पढ़ने के घंटों में वृद्धि / कमी

88 लाभार्थियों/परिवारों (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.-84, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-4, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. क.लि.-0) ने बताया कि रात के दौरान निरंतर विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण उन्हें शाम/रात में पढ़ने के विस्तारित घंटों का लाभ नहीं मिल सका।

(6) गाँवों के विद्युतीकरण से रात में गतिशीलता/सुरक्षा में वृद्धि

47 लाभार्थियों/परिवारों (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.-18, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-29, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. क.लि.-0) ने बताया कि रात में गतिशीलता/सुरक्षा में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ।

(7) निरंतर आपूर्ति के घंटों और वोल्टेज के उतार-चढ़ाव में वृद्धि/कमी

36 लाभार्थियों/परिवारों (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.-0, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-36, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. क.लि.-0) ने बताया कि विद्युत की आपूर्ति अनियमित थी, विद्युत के वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होता था और 25 (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.-12, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-13, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.- 0) परिवारों ने बताया कि विद्युत की आपूर्ति प्रतिदिन 12 घंटे से भी कम थी।

निर्गमन सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने इस बात का संज्ञान लिया।

अध्याय-V

अध्याय-V

योजना उपरांत विश्लेषण

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के वितरण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और मजबूती के साथ-साथ घरों के विद्युतीकरण और कनेक्शन जारी करने पर ध्यान केंद्रित किया। इन योजनाओं का समग्र उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गरीब परिवारों में सभी को विद्युत प्रदान करना था। इन योजनाओं की कार्यान्वयन अवधि (परियोजनाओं के समापन सहित) 2015-16 से 2021-22 तक थी। लेखापरीक्षा ने 2015-16 की शुरुआत से 2021-22 के अंत तक तीनों वितरण कम्पनियों के ग्रामीण क्षेत्रों मे उपभोक्ता आधार की वृद्धि का विश्लेषण किया। 2015-16 की शुरुआत से और 2021-22 के अंत तक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के विवरण के साथ डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के कारण जोड़े गए उपभोक्ताओं की स्थिति को नीचे **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: दिये गए कनेक्शनों का विवरण

क्र. सं.	वितरण कम्पनी का नाम	1 अप्रैल 2015 को घरेलू उपभोक्ताओं (ग्रामीण) की संख्या	31 मार्च 2022 तक घरेलू उपभोक्ताओं (ग्रामीण) की संख्या	2015-16 से 2021-22 के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं (ग्रामीण) में कुल वृद्धि की संख्या	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दिए गए कनेक्शनों की कुल संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत दिए गए कनेक्शनों की कुल संख्या (ग्रामीण)	डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के तहत दिए गए कनेक्शनों की कुल संख्या (ग्रामीण)	योजनाओं के कारण कुल कनेक्शन में वृद्धि (प्रतिशत में)
1.	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	11,68,380	20,69,703	9,01,323	97897	5,73,697	6,71,594	74.51
2.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	17,23,516	23,00,648	5,77,132	1,00,130	2,86,366	3,86,496	66.97
3.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	21,08,680	33,38,299	12,29,619	97,617	7,18,858	8,16,475	66.40
कुल		**50,00,576**	**77,08,650**	**27,08,074**	**2,95,644**	**15,78,921**[1]	**18,74,565**	**69.22**

***(स्रोत:** वितरण कम्पनियाँ द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)*

इस प्रकार, 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान मुख्य रूप से डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य में दिए गए 18,74,565 कनेक्शनों के कारण, वितरण कम्पनियों में 27,08,074 घरेलू उपभोक्ताओं (ग्रामीण) की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण उपभोक्ता आधार में वृद्धि और परिणामस्वरूप विद्युत की खपत में वृद्धि का विवरण निम्नलिखित **चार्ट 5.1 और चार्ट 5.2** में दिखाया गया है।

[1] इसके अतिरिक्त, योजना के तहत 57,994 शहरी गरीब परिवारों को कनेक्शन जारी किये गये।

चार्ट 5.1: योजनाओं के अंतर्गत जारी घरेलू कनेक्शन (ग्रामीण)

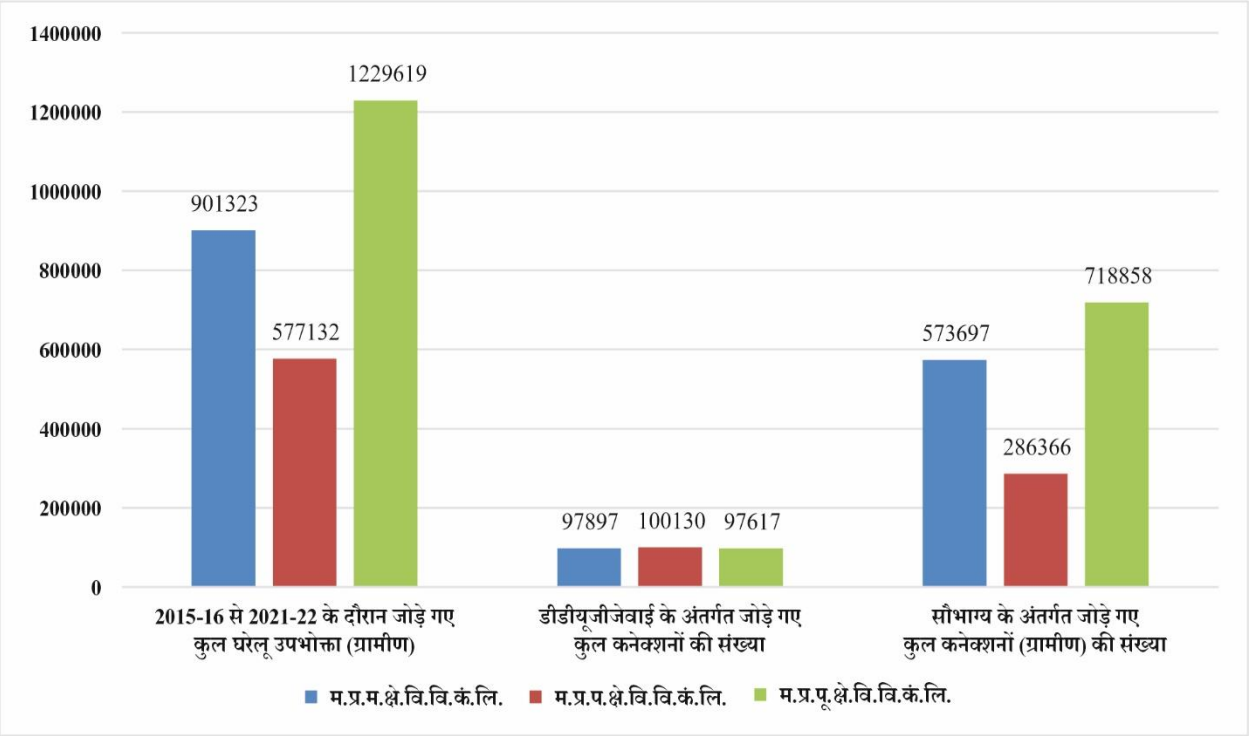

चार्ट 5.2: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की खपत में वृद्धि का विवरण

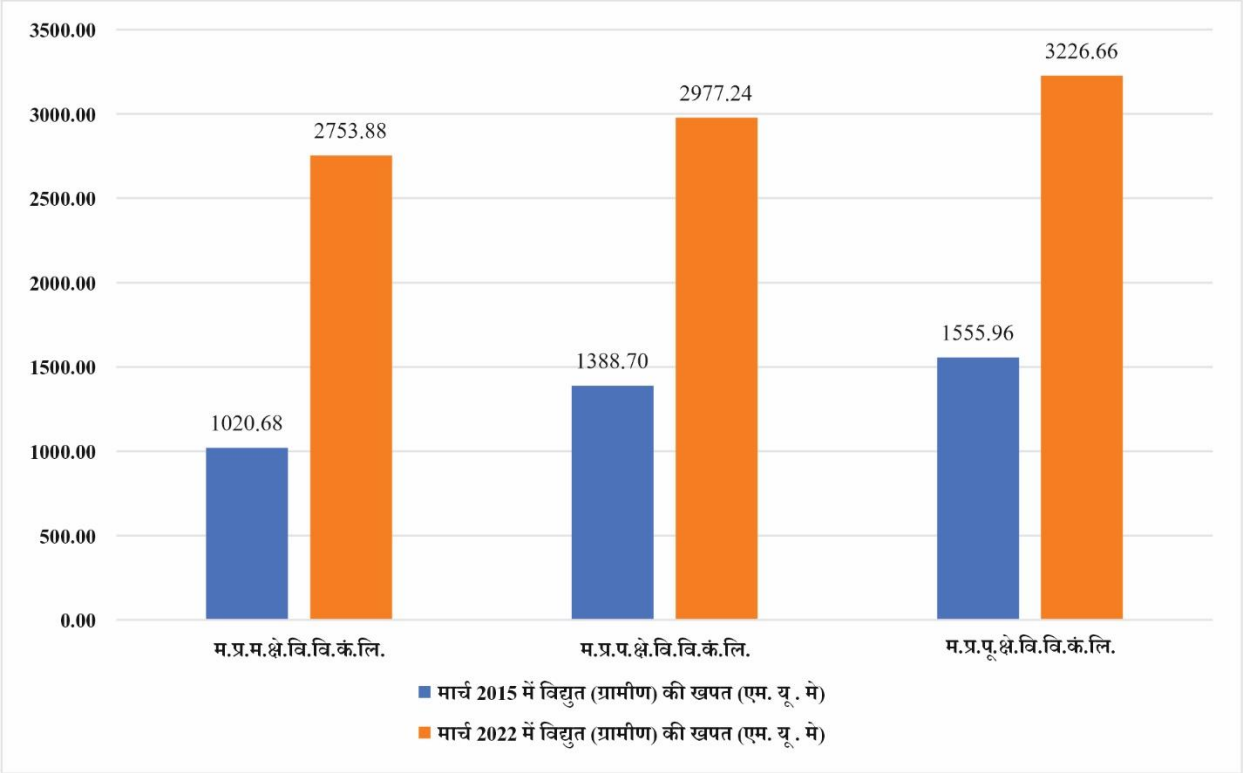

इसके अलावा, इन योजनाओं में सृजित संपत्ति के कुल मूल्य ₹ 4,694.98 करोड़ का वितरण कम्पनी-वार विवरण **चार्ट 5.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3: योजनाओं के अंतर्गत निर्मित बुनियादी ढांचे का मूल्य (₹ करोड़ में)

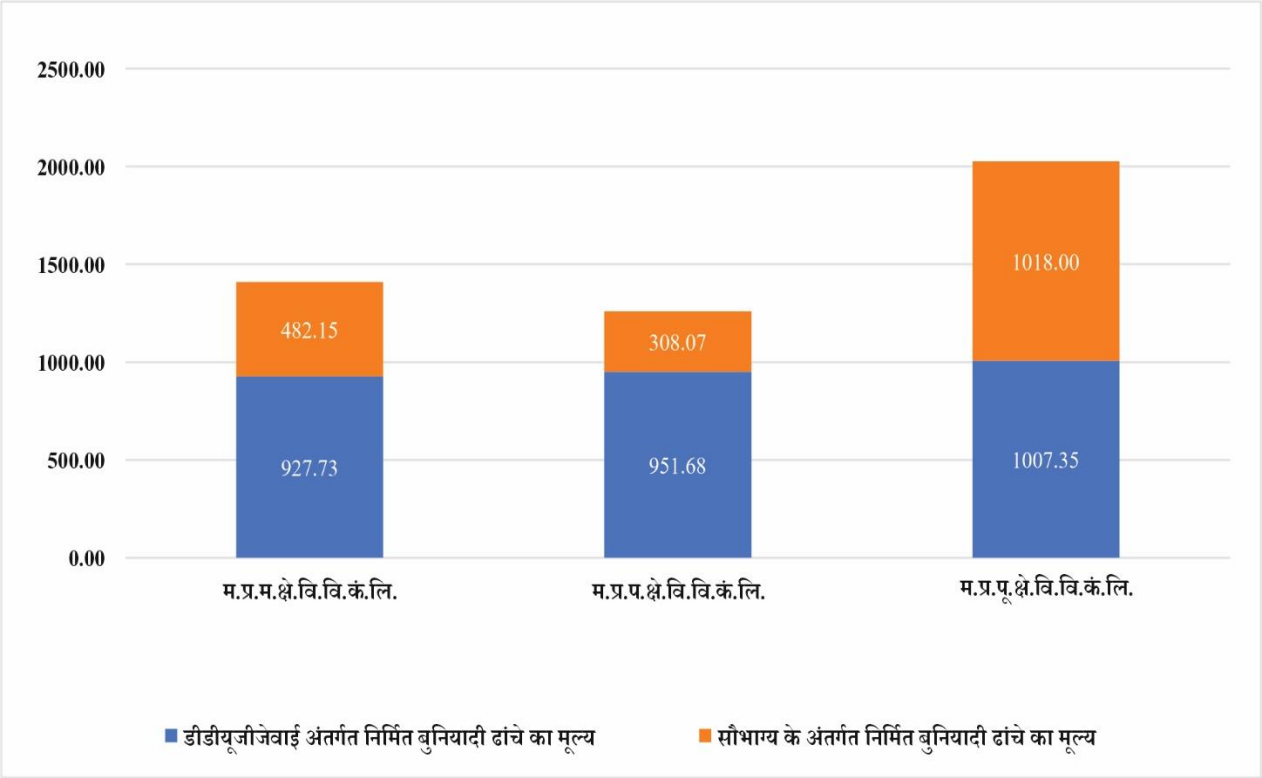

मध्य प्रदेश में योजनाओं के तहत कुल 19,32,559[2] घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए थे और म.प्र. शासन ने प्रमाणित किया था कि वितरण कम्पनियों[3] ने 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

विद्युत वितरण के स्थायी वाणिज्यिक संचालन के लिए डीडीयूजीजेवाई योजना ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता स्तर पर मीटरिंग पर जोर दिया। उपभोक्ता स्तर पर मीटरिंग के अलावा वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटरिंग की व्यवस्था से उचित ऊर्जा लेखांकन के लिए एक तंत्र बनाने में मदद मिलेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त करने के बावजूद, उपभोक्ताओं और वितरण ट्रांसफार्मर के मीटर रीडिंग न लेने के कारण विद्युत आपूर्ति के विवरण दर्ज करने का वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ था।

दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान, वितरण कंपनियों ने 4,18,451 मीटर सहित मीटर स्थापित करके परिवारों को कनेक्शन प्रदान किए, जो डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत मौजूदा बिना मीटर के उपभोक्ताओं के अलावा स्थापित किए गए थे। उपभोक्ताओं को मीटर के आकड़ों के अनुसार बिल दिया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्षेत्रिय इकाइयों ने बिलिंग की निगरानी के लिए डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के लाभार्थियों के अलग-अलग आकड़े नहीं रखे

[2] जिसमें योजना के तहत 57,994 शहरी गरीब परिवारों को घरेलू कनेक्शन जारी किये गये।

[3] म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि.-30 सितंबर 2018, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.-28 जुलाई 2018 और म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.-22 अक्टूबर 2022।

थे। हालाँकि, पूरे मार्च 2015 और मार्च 2022 में वितरण कम्पनियाँ के लिए अनंतिम बिलिंग[4] के प्रतिशत के रूप में तुलना से पता चलता है कि वितरण कम्पनियों (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. को छोड़कर) में अनंतिम बिलिंग में काफी वृद्धि हुई है, जैसा कि **चार्ट 5.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.4: वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को अनंतिम बिल दिखाए जाने वाले विवरण

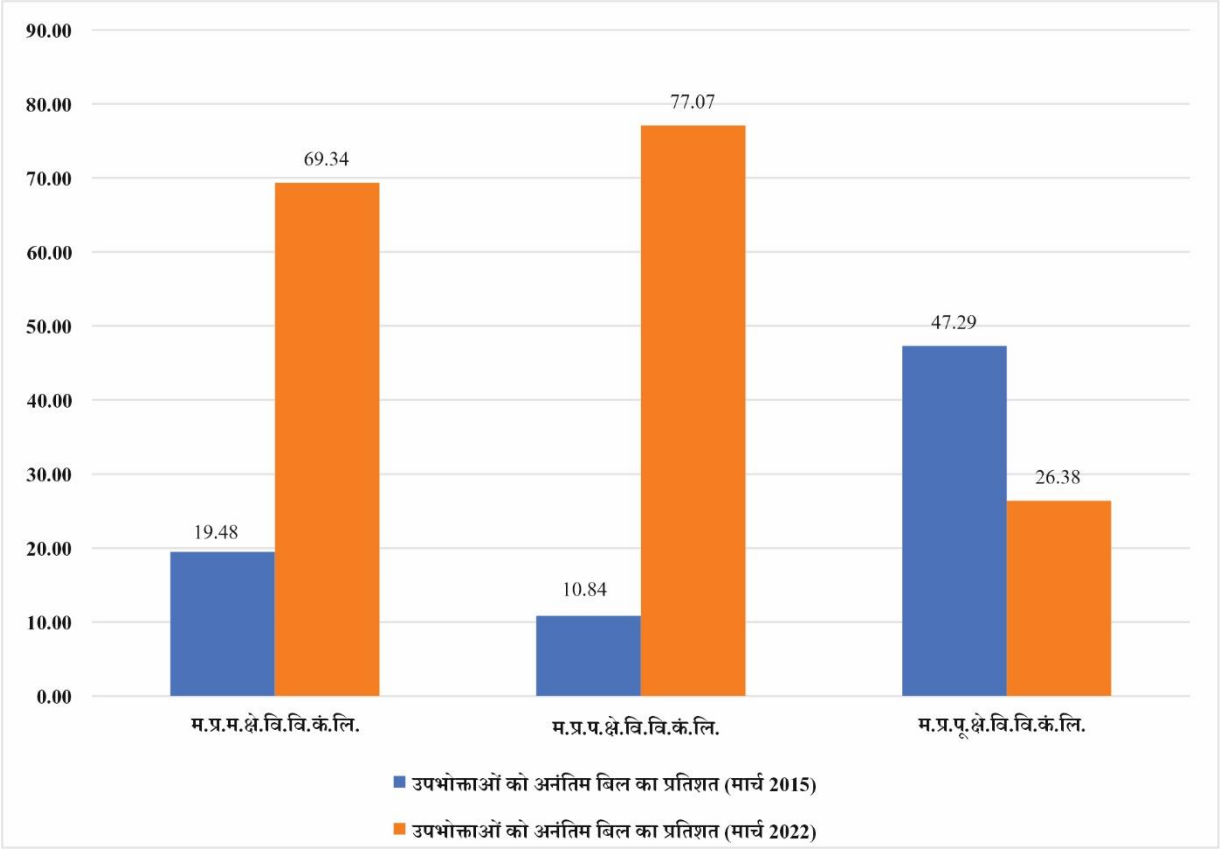

इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 26.38 से 77.07 प्रतिशत उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग के बिलिंग के कारण अनंतिम बिल भेजा जा रहा था।

निर्गमन सम्मेलन (जून 2023) में विभाग ने अनंतिम बिलिंग में कमी के लिए एक योजना बनाने का आश्वासन दिया।

[4] मीटर के अनुसार वास्तविक खपत के संदर्भ के बिना, अनुमानित आधार पर बिल बनाना।

निष्कर्ष: सार्वभौमिक विद्युतीकरण के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता आधार में पर्याप्त वृद्धि हुई। लेकिन उपभोक्ताओं/डीटीआर की मीटर रीडिंग लेने में प्रणालीगत खामियों के कारण पर्याप्त राजस्व वसूली सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

अनुशंसा: वितरण कम्पनियों को नए कनेक्शन के लिए सर्वोत्तम/अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं/डीटीआर मीटर रीडिंग को निरंतर लेने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

भोपाल
दिनांक : 28 अगस्त 2024

(प्रिया पारिख)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा द्वितीय)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 6 सितम्बर 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(कंडिका 1.6 में संदर्भित)

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के तहत वितरण कम्पनियों में निष्पादित भौतिक घटकों का विवरण दिखाने वाला पत्रक

क्र.सं.	घटकों का नाम	डीडीयूजीजेवाई				सौभाग्य			
		म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	कुल	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	कुल
1	नवीन 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र की संख्या	23	68	54	**145**	-	-	-	**-**
2	संवर्द्धन/अतिरिक्त पीटीआर की संख्या	41	159	114	**314**	-	-	-	**-**
3	11 केवी लाइन (सीकेएम)	9,163	6,175	5,774	**21,112**	3,171	2,089	7,339	**12,599**
4	डीटीआर की संख्या	9,412	6,915	8,285	**24,612**	4,459	3,115	7,630	**15,204**
5	एलटी लाइन (सीकेएम)	8,262	10,180	7,976	**26,418**	3,800	6,270	11,086	**21,156**
6	अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की मीटरिंग की संख्या	1,495	1,27,191	52,280	**1,80,966**	-	-	-	**-**
7	खराब मीटरों को बदलने की संख्या	4,909	95,849	1,36,757	**2,37,515**	-	-	-	**-**
8	जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या	97,897	1,00,090	97,617	**2,95,604**	5,92,961	3,01,404	7,42,550	**16,36,915**

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.1 में संदर्भित)

13 नमूना परियोजनाओं में डीडीयूजीजेवाई के कार्य निष्पादन का ब्योरा दिखाने वाला पत्रक

चयनित परियोजनाओं का नाम		म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.					म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.				म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.				कुल
		बैतूल	भोपाल	रायसेन	राजगढ़	विदिशा	धार	झाबुआ	खरगौन	रतलाम	बालाघाट	डिंडौरी	मंडला	शहडोल	
स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)		144.02	30.83	26.58	98.75	36.26	121.45	33.58	115.67	60.22	44.24	15.45	16.15	12.53	**755.73**
वास्तविक निष्पादित लागत (₹ करोड़ में)		140.18	30.51	26.20	90.62	33.14	129.36	31.91	111.7	60.61	46.25	16.72	17.41	12.39	**747.00**
नया 33/11 केवी उप स्टेशन (मात्रा संख्या में)	स्वीकृत	1	1	1	2	2	5	1	5	4	0	0	0	0	**22**
	निष्पादित	1	1	1	2	1	6	1	5	4	0	0	0	0	**22**
33/11 केवी उप स्टेशन का विस्तार (मात्रा संख्या में)	स्वीकृत	5	3	6	4	3	20	7	12	9	6	0	0	2	**77**
	निष्पादित	0	3	0	0	0	19	4	12	9	6	0	0	2	**55**
फीडर विभक्तिकरण (मात्रा संख्या में)	स्वीकृत	128	9	25	13	17	116	23	17	17	6	5	5	0	**381**
	निष्पादित	100	3	10	4	3	114	30	32	50	6	5	4	0	**361**
11 केवी लाइन (मात्रा सीकेएम में)	स्वीकृत	2	238	250	591	427	1,491	208	1,081	421	358	215	173	35	**5,490**
	निष्पादित	103	253	295	660	319	1,570	181	804	347	302	748	155	85	**5,822**
डीटीआर (मात्रा संख्या में)	स्वीकृत	2,370	473	169	859	193	830	256	1,879	565	352	165	180	65	**8,356**
	निष्पादित	1,495	322	299	806	381	1,304	169	1,309	472	392	177	152	88	**7,366**
एलटी लाइन (मात्रा सीकेएम में)	स्वीकृत	876	147	56	384	75	1,488	310	1,221	293	200	131	150	49	**5,380**
	निष्पादित	1,441	251	281	1,168	327	1,423	781	1,558	359	315	143	181	92	**8,320**
उपभोक्ता मीटरिंग (मात्रा संख्या में)	स्वीकृत	20,817	1,034	3,597	17,190	17,478	93,090	61,336	0	14,286	66,958	7,874	15,125	12,576	**331,361**
	निष्पादित	4,909	0	896	0	0	35,000	10,990	296	10,039	59,940	4,321	8,168	9,350	**143,909**
नये कनेक्शन (मात्रा संख्या में)	स्वीकृत	29,870	4,300	0	88,690	0	21	0	36,743	2,753	0	0	41	177	**1,62,595**
	निष्पादित	6,149	5,343	502	14,399	7,041	21	0	22,518	2,753	0	0	80	1,521	**60,327**

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका 2.2.2 में संदर्भित)

डीडीयूजीजेवाई के तहत डीटीआर और उपभोक्ताओं की मीटरिंग की दोषपूर्ण योजना को दर्शाने वाला पत्रक

वितरण कंपनी का नाम	परियोजनाओं का नाम	डीटीआर मीटरिंग					उपभोक्ता मीटरिंग				
		बिना मीटर वाले डीटीआर की संख्या	मीटरिंग के लिए नियोजित डीटीआर की संख्या (डीपीआर के अनुसार)	डीटीआर मीटरिंग निष्पादित	वास्तविक संख्या से नियोजित का प्रतिशत	नियोजित से क्रियान्वित का प्रतिशत	बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या	नियोजित उपभोक्ता मीटरिंग की संख्या (डीपीआर के अनुसार)	निष्पादित उपभोक्ता मीटरिंग की संख्या	नियोजित का प्रतिशत वास्तविक संख्या से	नियोजित से निष्पादित का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6=4/3%	7=5/4%	8	9	10	11=9/8%	12=10/9%
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बैतूल	6,404	500	0	8	0	56,434	12,947	0	23	0
	भोपाल	5,225	150	0	3	0	2,080	980	0	5	0
	रायसेन	10,011	500	0	5	0	18,737	2,815	896	15	32
	राजगढ़	9,353	750	0	8	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विदिशा	3,874	500	0	13	0	15,894	15,778	0	99	0
	योग	**34,867**	**2,400**	**0**	**7**	**0**	**93,145**	**32,520**	**896**	**29**	**3**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	धार	15,841	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	झाबुआ	3,885	0	0	0	लागू नहीं	87,210	60,888	10,990	70	18
	खरगौन	7,979	0	0	0	लागू नहीं	8,198	0	0	0	लागू नहीं
	रतलाम	12,412	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	योग	**40,117**	**0**	**0**	**0**	**लागू नहीं**	**95,408**	**60,888**	**10,990**	**64**	**18**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बालाघाट	8,069	0	0	0	लागू नहीं	17,755	4,330	0	24	0
	डिंडौरी	2,512	0	0	0	लागू नहीं	13,643	1,040	3,352	8	322
	मंडला	2,258	0	0	0	लागू नहीं	21,877	2,016	1,394	9	69
	शहडोल	1,487	0	0	0	लागू नहीं	41,949	1,820	9,350	4	514
	योग	**14,326**	**0**	**0**	**0**	**लागू नहीं**	**95,224**	**9,206**	**14,096**	**10**	**153**
कुल योग		**89,310**	**2,400**	**0**	**3**	**लागू नहीं**	**2,83,777**	**1,02,614**	**25,982**	**34**	**25**

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका 2.3.1 में संदर्भित)

डीपीआर में स्वीकृत लेकिन कार्यान्वयन से वंचित गांवों का ब्योरा दिखाने वाला पत्रक

वितरण कम्पनी का नाम	परियोजनाओं का नाम	डीपीआर में शामिल किये गये गांवों की कुल संख्या	डीपीआर से निष्पादित ग्रामों की संख्या	डीपीआर से निष्पादित न किये गये गांवों की संख्या	स्वीकृत डीपीआर के अतिरिक्त निष्पादित ग्रामों की संख्या	शामिल किये गये कुल गाँव
1	**2**	**3**	**4**	**5=3-4**	**6**	**7=4+6**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बैतूल	897	389	508	161	550
	भोपाल	451	217	234	27	244
	रायसेन	317	32	285	128	160
	राजगढ़	1,695	842	853	41	883
	विदिशा	179	40	139	266	306
	योग	**3,539**	**1,520**	**2,019**	**623**	**2,143**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	धार	800	571	229	0	571
	झाबुआ	293	159	134	161	320
	खरगोन	1348	695	653	130	825
	रतलाम	337	208	129	105	313
	योग	**2,778**	**1,633**	**1,145**	**396**	**2,029**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.	डिंडौरी	195	166	29	0	166
	मंडला	113	113	0	28	141
	शहडोल	78	78	0	12	90
	योग	**386**	**357**	**29**	**40**	**397**
कुल योग		**6,703**	**3,510**	**3,193**	**1,059**	**4,569**

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.1 में संदर्भित)

सौभाग्य के तहत 13 चयनित परियोजनाओं में निष्पादित वित्तीय और भौतिक घटकों का ब्योरा दिखाने वाला पत्रक

वितरण कम्पनी का नाम	चयनित परियोजनाओं का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	वास्तविक निष्पादित लागत (₹ करोड़ में)	11 केवी लाइन (सीकेएम में)		डीटीआर (संख्या में)		एलटी लाइन (सीकेएम में)		नया कनेक्शन बी.पी.एल (संख्या में)	
				स्वीकृत	निष्पादित	स्वीकृत	निष्पादित	स्वीकृत	निष्पादित	स्वीकृत	निष्पादित
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	बैतूल	24	25.17	101	86	111	111	171	170	34,498	32,851
	भोपाल	10.34	8.79	81	36	79	13	30	27	23,518	16,550
	रायसेन	42.67	29.84	272	207	108	78	126	215	28,012	47,177
	राजगढ़	36.91	38.49	139	148	228	219	128	298	68,859	62,478
	विदिशा	29.54	27.95	174	160	197	190	318	172	47,993	48,724
योग		**143.46**	**130.24**	**767**	**637**	**723**	**611**	**773**	**882**	**2,02,880**	**2,07,780**
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	धार	55.11	43.48	243	299	279	81	579	915	45,162	46,116
	झाबुआ	36.64	35.47	81	67	193	170	410	785	51,838	48,645
	खरगौन	44.75	39.88	262	445	689	765	762	789	21,469	20,855
	रतलाम	28.57	29.15	114	118	211	209	369	614	27,810	27,225
योग		**165.07**	**147.98**	**700**	**929**	**1,372**	**1,225**	**2,119**	**3,103**	**1,46,279**	**1,42,841**
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लि.	बालाघाट	42.89	36.53	385	385	267	287	406	404	48,017	44,967
	डिंडौरी	58.7	63.80	356	356	441	441	962	962	34,164	32,011
	मंडला	64.1	64.06	426	306	471	862	1035	1014	32,426	36,402
	शहडोल	51.94	53.14	330	205	322	175	649	350	41,075	45,052
योग		**217.63**	**217.53**	**1,497**	**1,252**	**1,501**	**1,765**	**3,052**	**2,730**	**1,55,682**	**1,58,432**
कुल योग		**526.16**	**495.75**	**2,964**	**2,818**	**3,596**	**3,601**	**5,944**	**6,715**	**5,04,841**	**5,09,053**

परिशिष्ट 3.2

(कंडिका 3.3.1 में संदर्भित)

वितरण कंपनियों में बिना टेंडर के कार्यों के निष्पादन का ब्योरा दर्शाने वाला पत्रक

वितरण कम्पनी का नाम	जिले का नाम	कार्य आदेश का विवरण	जारी किए गए कार्यादेश की संख्या	उपलब्ध कराए गए कनेक्शनों की संख्या	कार्यादेश का मूल्य (₹ करोड़ में)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	धार	घरों में कनेक्शन उपलब्ध कराना	15	3,990	0.17
	रतलाम	घरों में कनेक्शन उपलब्ध कराना	16	2,834	0.54
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लि.	शहडोल	घरों में कनेक्शन उपलब्ध कराना	843	31,712	11.91
		अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे का निर्माण	829	-	7.91
	बालाघाट	घरों में कनेक्शन उपलब्ध कराना	744	39,722	9.38
	मंडला	घरों में कनेक्शन उपलब्ध कराना	686	34,179	10.86
		अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे का निर्माण	319	-	3.33
	डिंडौरी	घरों में कनेक्शन उपलब्ध कराना	628	25,617	6.52
कुल			**4,080**	**1,38,054**	**50.62**

परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.3.8 में संदर्भित)

सौर ऊर्जा पैक की अनुचित क्षमता की स्थापना का ब्योरा दर्शाने वाला पत्रक

वितरण कम्पनी का नाम	जिले का नाम	कुल स्थापित सौर ऊर्जा पैक की संख्या	अनुपयुक्त क्षमता के सौर ऊर्जा पैक की संख्या (250 वाट पीक से कम)	स्थापित क्षमता (वाट पीक में)	प्रति सोलर पावर पैक की दर (₹ में)	कुल मूल्य (₹ में)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.	रायसेन	425	425	200	38,367	1,63,05,175
	बैतूल	587	587	200	31,348	1,84,01,276
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.	झाबुआ	50	50	200	25,830	12,91,500
	खरगोन	270	270	200	25,830	69,74,100
	धार	25	25	200	25,830	6,45,750
	रतलाम	70	70	50	14,585	10,20,950
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लि.	शहडोल	991	991	200	37,701	3,73,61,691
	बालाघाट	96	96	200	37,701	36,19,296
	मंडला	250	250	200	37,701	94,25,250
	डिंडौरी	200	200	200	37,701	75,40,200
कुल		**2,964**	**2,964**			**10,25,85,988**

परिशिष्ट 4.1

(अध्याय 4 में संदर्भित)

लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र का प्रारूप

लाभार्थियों का सर्वेक्षण:

क) राज्य का नाम:	
ख) जिले का नाम:	
ग) ब्लॉक का नाम:	
घ) गांव का नाम:	
ई) लाभार्थी/कनेक्शन धारक का नाम:	
च) राशन कार्ड नंबर (बीपीएल/एपीएल)	
1) आपके परिवार में सदस्यों की संख्या:	
2) ग्राम पंचायत/राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कनेक्शन:	
3) क्या कनेक्शन प्रदान किया गया था:: क) वितरण कंपनी द्वारा ही? ख) लाभार्थी के अनुरोध पर?	
ग) कनेक्शन की स्थापना की तारीख	
4) कनेक्शन के ऊर्जाकरण की तिथि	
5) क्या कोई सीएफएल निःशुल्क प्रदान किया गया था?	
6) क्या कनेक्शन डीडीयूजीजेवीवाई या सौभाग्य योजना के तहत प्रदान किया गया है?	
7) (i) कृषि प्रयोजनों के लिए कितने घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान की गई? समय निर्दिष्ट करें (...सुबह से...दोपहर तक) (ii) गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कितने घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान की गई? समय निर्दिष्ट करें (...सुबह से...दोपहर तक)	
8) क्या कनेक्शन के समय मीटर उपलब्ध कराया गया है?	
9) आप डीडीयूजीजेवीवाई या सौभाग्य के बारे में क्या जानते हैं?	
10) क्या ग्राम स्तर पर कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया? (कृपया यह प्रश्न पंचायत स्तर पर पूछें)	
11) आप इस गांव में कब से रह रहे हैं?	
12) क्या आपको बिजली का बिल मिल रहा है? यदि हां तो कैसे?	
13) क्या आप बिजली शुल्क/बिल का भुगतान कर रहे हैं? यदि हाँ, तो अंतिम बिल भुगतान का विवरण।	
14) क्या कनेक्शन के लिए आपके द्वारा कोई राशि का भुगतान किया गया था और यदि हां, तो कितना?	
15) यदि कनेक्शन/आपूर्ति/मीटर/अधिक बिजली बिल आदि में कोई खराबी है तो शिकायत दर्ज करने में कितना समय लगेगा:	
16) आय का स्रोत (कृषि, पशुधन, व्यवसाय जैसे आटा मिलें, सेवा आदि)	
17) क्या गाँव/दुकानों के विद्युतीकरण/बिजली पंप सेट के उपयोग के बाद आय में कोई वृद्धि हुई है।	
18) क्या घर/गांव में बिजली के कारण व्यय में कोई वृद्धि/कमी हुई है?	
19) डीजल, जेन सेट, डीजल पंप सेट आदि का कम से कम उपयोग करने से मासिक व्यय पर प्रभाव।	

20) पंखा, आइरन, टेलीविजन, फ्रिज आदि जैसी किसी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु का उपयोग घर में बढ़ गये है।	
21) घर में बिजली कनेक्शन से पहले और घर में बिजली आने के बाद अध्ययन के घंटों की तुलना	
22) क्या बिजली आपूर्ति में कोई सुधार हुआ है? (i) यदि हां तो कितने घंटे लगातार बिजली आपूर्ति की जा रही है? (ii) क्या गाँव में बिजली का कोई वोल्टेज उतार-चढ़ाव है? पूरी जानकारी। (iii) क्या पढ़ाई के घंटे/टीवी देखने/घरेलू उपकरणों के उपयोग में आराम /पेशे/ग्रामीण उद्योगों आदि में कोई सुधार हुआ है? (iv) क्या उचित वोल्टेज पर बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इनवर्टर आदि का उपयोग किया जा रहा है?	
23) क्या गाँव के विद्युतीकरण के कारण रात में गतिशीलता/सुरक्षा में कोई वृद्धि हुई है? यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं।	
24) क्या डीजल के स्थान पर बिजली के उपयोग, जेनसेट संचालन और वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से ब्रेक डाउन में कमी के कारण व्यय लागत में कोई कमी आई है?	
25) डीडीयूजीजेवीवाई के कार्यान्वयन से संबंधित लाभार्थी की कोई भी शिकायत/सुझाव:	

लाभार्थी के हस्ताक्षर:

लाभार्थी का नाम:

मोबाइल नंबर: **लेखापरीक्षा दल के व.ले.प.अ./ले.प.अ./स.ले.प.अ. का नाम एवं हस्ताक्षर**

सौभाग्य

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2024
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh